लखनऊ

शनिवार, 8 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 339

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

धन कमाने से घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन दुआएं कमाने से ख़ुशी और प्यार आता है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

भारतीय वायुसेना के लिए 3.25 लाख करोड़ की महाडील, फ्रांस ने दिया 114 राफेल का प्रस्ताव

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को कई गुना बढ़ाने और आसमान में अपनी धाक और मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक महाडील पर काम तेज हो गया है। फ्रांस की मशहूर विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत को 114 मल्टीरोल राफेल फाइटर जेट्स देने के लिए अपना तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव भारत सरकार को सौंप दिया है। करीब 3 .25 लाख करोड़ रुपये की इस संभावित डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन विमानों का निर्माण सीधे तौर पर 'मेक इन इंडिया' पहल से जुड़ा होगा। इसके तहत 114 में से 94 लड़ाकू विमान भारत की सरजमीं पर ही एक भारतीय पार्टनर कंपनी के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की विंग और वायुसेना ने इस बेहद अहम प्रपोजल का बारीकी से मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है। मई महीने में भारत द्वारा भेजे गए 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' के जवाब में फ्रांस ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भारी जोर दिया गया है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह डील 'मेक इन इंडिया' के बिना मुमकिन नहीं है। इस समझौते के तहत डसॉल्ट एविएशन के साथ-साथ इंजन बनाने वाली कंपनी सफरान एवियोनिक्स देने वाली थेल्स और हथियार निर्माता एमबीडीए भी अपनी अहम तकनीक भारत को ट्रांसफर करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद एयरफ्रेम, इंजन और एवियोनिक्स में 55% से 60% तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे भारत का रक्षा उद्योग इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स की मजबूत फ्लीट मौजूद है, जिन्हें 2015 के सौदे के तहत शामिल किया गया था।

जेएसपीसी परीक्षा धांधली : सीआईडी ने मुख्य आरोपी अभय तिवारी के ससुर को लिया हिरासत में

रांची। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस परीक्षा में गड़बड़ी और परीक्षार्थियों से अवैध धन उगाही मामले की जांच कर रही सीआईडी की विशेष टीम ने कार्रवाई और तेज कर दी है। सीआईडी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित हथबोर गांव में छापेमारी कर मामले के मुख्य आरोपी मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय तिवारी के ससुर विकास पांडेय को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। विकास पांडेय स्थानीय सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। सीआईडी की टीम ने हथबोर स्थित आवास पर विकास पांडेय से घंटों गहन पूछताछ की और फिर उन्हें आगे की जांच के लिए अपने साथ ले आई है। जांच एजेंसी मुख्य रूप से अभय तिवारी के दोनों साले (विकास पांडेय के पुत्रों) की भूमिका और उनके ठिकानों की पड़ताल कर रही है। सीआईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद से ही दोनों फरार हैं। एजेंसियों को संदेह है कि कानूनी शिकंजे से बचने के लिए वे विदेश भाग चुके हैं, जिसकी पुष्टि के लिए उनके यात्रा दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इस कार्रवाई के साथ ही सीआईडी और वित्तीय खुफिया शाखा अब आरोपी परिवार की अचल संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की भी गहन जांच कर रही है।

आवाजें एक साथ उठती हैं तभी सरकार झुकती है : राहुल गांधी ने पेपर लीक पर भाजपा को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। शुक्रवार को प्रयागराज में अपने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तभी झुकती है जब आवाज़ें एक साथ उठती हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परीक्षा के पेपर लीक होने के ख़िलाफ़ छात्रों के लगातार विरोध-प्रदर्शनों ने सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए मजबूर किया। गुरुवार को X पर एक पोस्ट में, गांधी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर महीनों तक चले विरोध-प्रदर्शनों के बाद पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का ज़िक्र किया और कहा कि सामूहिक कार्रवाई ने सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया। गांधी ने कहा कि प्रयागराज वह शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो गया है। छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है; समस्या उस सिस्टम में है जो उनकी मेहनत की कद्र नहीं करता। उन्होंने नौकरी के उम्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में पेपर लीक, रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों में लंबी देरी का ज़िक्र किया। कोटा और देहरादून में छात्रों के साथ अपनी हालिया बातचीत का ज़िक्र करते हुए, गांधी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में भी ऐसी ही शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने वाले छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आखिरकार, एक मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। यह सरकार तभी झुकती है जब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं।' उन्होंने छात्रों को 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रयागराज के KP ग्राउंड में होने वाली बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

'कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं'

सीएम योगी ने अखिलेश पर कसा तंज, बोले- बबुआ भी यही करते थे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं। बबुआ भी यही करते थे। वो दोपहर 12 बजे सो कर उठते थे। दो बजे तैयार होते थे। पांच बजते-बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और शाम 7 बजे महफिल सज जाती थी। देश प्रदेश के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही कहां होता था। प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल तो ये था कि महिलाओं को सबसे बड़ा खतरा इन्हीं सपाइयों से ही था।

मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के अवसर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने का कि जब सरकारें प्रदेश के विकास के लिए काम करती हैं तो उसका लाभ समाज के हर तबके को मिलता है।

इसके पहले सीएम योगी ने एक्स पर कहा कि आज उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत और हमारे कर्मठ बुनकर साथियों की अप्रतिम प्रतिभाओं को नमन करने का दिन है। 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के अवसर पर लखनऊ में आयोजित समारोह में हमारे उत्कृष्ट बुनकर भाई-बहनों को 'संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार' से सम्मानित करने का सौभाग्य मिलेगा। साथ ही, 'मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना' तथा 'झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना' के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए जाएंगे। इसके उपरांत, जनपद अम्बेडकरनगर के सर्वांगीण विकास के लिए ₹706 करोड़ से अधिक की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास होगा। साथ ही, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र, प्रमाण-पत्र और चेक भी वितरित करूंगा। डबल इंजन सरकार हुनरमंद हाथों को आधुनिक संसाधन, बाजार और सम्मान प्रदान कर 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के निर्माण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

एसी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं , केंद्र ने एससी में दाखिल किया हलफनामा, याचिकाएं खारिज करने की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में आय के आधार पर 'क्रीमी लेयर' लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में साफ कर दिया है कि स्ट और स्ज्ज वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता है। सरकार ने अदालत से इन सभी याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया है और कहा है कि नीति बनाना पूरी तरह से कार्यपालिका का काम है, जो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि स्ट, स्ज्ज और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मानदंड अलग-अलग हैं। अनुसूचित जातियों ने ऐतिहासिक रूप से छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों का सामना किया है, जबकि अनुसूचित जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति और भौगोलिक अलगाव के कारण पिछड़ी रही हैं। सरकार ने तर्क दिया है कि इन वर्गों की पहचान केवल आर्थिक स्थिति पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई है। क्रीमी लेयर का नियम मुख्य रूप से 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले के तहत ओबीसी वर्गों के संपन्न लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए लागू किया गया था। दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब वकील अश्विनी उपाध्याय और रामाशंकर प्रजापति सहित अन्य लोगों ने याचिकाएं दाखिल कर एससी/एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू करने की मांग की। इससे पहले 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से स्ट और स्ज्ज में उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी थी।

बिना गहन शोध और समीक्षा के नीतिगत बदलाव संभव नहीं

केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि आरक्षण नीति में कोई भी संशोधन या आय के आधार पर उप-कोटा तय करने से पहले एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक अध्ययन और गहन समीक्षा की जरूरत होती है। सरकार के मुताबिक, कोर्ट के किसी भी पिछले आदेश में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि क्रीमी लेयर का नियम एससी और एसटी पर भी लागू किया जाना चाहिए। अतीत में क्रीमी लेयर के संदर्भ में कही गई बातें मुख्य रूप से ओबीसी और एसईबीसी वर्गों के संदर्भ में ही सामान्य टिप्पणियां थीं।

अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया जाएगा बेटा अबान

आर्यावर्त क्रांति

झांसी। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का शव शुक्रवार सुबह प्रयागराज पहुंचा। सूत्रों ने बताया कि अबान के शव को कसारी-मसारी स्थित उसी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा जहां उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और बड़े भाई असद को दफनाया गया था।

अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद और उसके साथी शाकिर उर्फ सोनू की गुरुवार को झांसी-कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में मौत हुई थी। झांसी में पोस्टमार्टम की कागजी और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद परिजन एंबुलेंस के जरिए दोनों के शवों को लेकर प्रयागराज पहुंचे हैं।

फिलहाल अबान के शव को हटवा स्थित उसकी बुआ के घर पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद अबान अहमद के शव को कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। अबान की कब्र फिलहाल खोद ली गई है। अतीक अहमद की कब्र के पास ही आबान की कब्र बनाई गई है। देर रात तक कब्र खोदने का काम चलता रहा। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस के अनुसार, प्रयागराज से झांसी आ रही अबान की क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि हादसे में अतीक के बेटे अबान समेत दो की मौत हो गई। अन्य घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

केजरीवाल का बड़ा आरोप : क्या 'चंदाचोर' और 'बेअदबी पार्टी' का पंजाब में हुआ गठबंधन?

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बीच हुई बैठक की खबरों के बीच, 2027 के पंजाब चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की अटकलों को हवा दी। केजरीवाल ने X पर पोस्ट किया कि ना ना करते प्यार तुमही से कर बैठे। तो क्या चंदाचोर पार्टी और बेअदबी पार्टी के बीच गठबंधन हो रहा है?

भाजपा ने पहले एसएडी के साथ गठबंधन से इनकार किया था और कहा था कि पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी। जून में भाजपा की पंजाब इकाई की बैठक के बाद, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, 'हमने पंजाब की राजनीति पर चर्चा की। यह एक बहुत अच्छी बैठक थी। पंजाब के लिए हमारा एकमात्र एजेंडा विकास है। हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे; अभी गठबंधन की कोई बात नहीं है। हम पंजाब में भाजपा की सरकार बनाएंगे।' भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पंजाब में खिलते कमल का आह्वान किया है। अकाली दल द्वारा 2021 में तीन कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शनों के बीच एनडीए छोड़ने से पहले भाजपा और एसएडी ने पंजाब में गठबंधन सरकारें बनाई थीं। हालांकि, 2022 के पिछले चुनावों में SAD और BJP विधानसभा में क्रमशः तीन और दो सीटों तक ही सीमित रह गईं, जबकि AAP ने 92 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। पंजाब में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस ने BJP और AAP के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है।

सीआरपीएफ में मानसिक तनाव का दौर, 5 सालों में 281 जवानों ने की खुदकुशी, 2025 में टूटे सभी रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवानों को लेकर एक बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हमेशा आतंकियों और नक्सलियों से लोहा लेने वाले हमारे बहादुर जवान अब मानसिक तनाव और निजी परेशानियों से हार रहे हैं। हाल ही में सामने आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीते पांच सालों में जवानों की आत्महत्या के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2025 में खुदकुशी के आंकड़े अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसने सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की नींद उड़ा दी है।

ड्यूटी के दौरान सबसे ज्यादा मौतें, सिपाही वर्ग में बढ़ा तनाव

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, साल 2025 में कुल 59 सीआरपीएफ जवानों ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली, जो पिछले पांच सालों में एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अपनी जान देने वालों में 80 प्रतिशत से अधिक जवान सिपाही रैंक के थे। आंकड़ों की गहराई में जाएं तो 2021 से 2025 के बीच सामने आए 262 मामलों में से 202 मामलों (करीब 77 प्रतिशत) में जवानों ने तब यह खौफनाक कदम उठाया, जब वे अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। बाकी की घटनाएं छुट्टी पर रहने के दौरान हुईं।

घर की कलह और नौकरी का भारी दबाव बन रहा जानलेवा

इस गंभीर विषय पर हालांकि बल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सीआरपीएफ के कुछ अधिकारियों ने बताया कि जवानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि आत्महत्या के अधिकतर मामलों के पीछे पारिवारिक विवाद और घर की परेशानियां मुख्य कारण रही हैं। इसके साथ ही, नौकरी की सख्त दिनचर्या और कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी ने जवानों के मानसिक तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि लगभग 3.25 लाख की क्षमता वाले इस बल के 95 से 97 प्रतिशत जवान हर समय मोर्चे पर डटे रहते हैं, चाहे वह आतंकवादियों से निपटना हो या देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हो।

'आपने आधी जिंदगी इसलिए बिताई ताकि आपको भुला दिया जाए'

स्मृति ईरानी का मातृत्व पर भावुक बयान हुआ वायरल

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मां बनने के अनुभव, वर्किंग मदर्स (कामकाजी माताओं) की दैनिक चुनौतियों और बच्चों के बड़े होकर आत्मनिर्भर होने की भावनात्मक सच्चाई पर खुलकर अपने विचार साझा किए। 50 वर्षीया स्मृति ईरानी का यह प्रेरक और भावुक भाषण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अब तक 1 लाख 24 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है। ईरानी ने कहा कि ज़्यादातर वर्किंग मदर्स को उन सालों के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता क्योंकि वे हर चीज़ को एक साथ संभालने में ही लगी रहती हैं। उन्होंने कहा,'उन्हें काम पूरा करना होता था। उन्हें अपने बच्चे को खाना खिलाना होता था। उन्हें यह पक्का करना होता था कि होमवर्क हो गया है, और यह भी कि उनकी PPT भी तैयार है। कई रातें ऐसी गुज़रती थीं जब वे सो भी नहीं पाती थीं।' उन्होंने इस बात पर मज़ाक भी किया कि बच्चे कितनी तेज़ी से बड़े हो जाते हैं - पहले उन्हें हर समय देखभाल की ज़रूरत होती है और फिर वे टीनएजर बन जाते हैं और पलटकर जवाब देने लगते हैं। ईरानी ने कहा, 'आप में से कितने लोग सोचते होंगे कि 'अभी तो मैं नैपी साफ़ कर रही थी और अब यह बच्चा मुझसे पलटकर बात कर रहा है?' उनकी इस बात पर दर्शकों ने प्रतिक्रिया दी।

'मां होने का एहसास ऐसा ही होता है'

हालांकि, ईरानी के लिए मां बनने का मतलब सिर्फ़ बच्चों की परवरिश में बिताए गए साल नहीं हैं। उन्होंने इसे एक लंबा सफ़र बताया, जिसका असली मतलब तब समझ आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। उन्होंने कहा कि कई मांएं उन सालों के बारे में तब सोचती हैं जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। उन्होंने कहा, 'मां होने का एहसास ऐसा ही होता है। यह एक ऐसा काम है जो तभी पूरा माना जाता है जब बच्चे को आपकी ज़रूरत न रहे। और यही सबसे दुखद बात है।' ईरानी ने इस बारे में भी बात की कि बेटियां और बेटे अपनी मां को किस तरह याद करते हैं। उन्होंने कहा, 'बेटी को तब याद आती है जब उसका अपना बच्चा होता है,' और आगे कहा कि बेटे शायद अपनी मां की अहमियत बहुत बाद में समझते हैं।

'आपने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा इसलिए बिताया ताकि बाकी आधे हिस्से में आपको भुला दिया जाए'

ईरानी ने इस बात पर भी अपनी राय रखी कि बेटियां और बेटे अपनी मां को किन अलग-अलग तरीकों से याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'और आपके पास बस एक तस्वीर, एक याद या एक टेक्स्ट मैसेज ही बचेगा। आप इसी चीज़ को बड़ा कर रही हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा इसलिए बिताया ताकि बाकी आधे हिस्से में आपको भुला दिया जाए।' इसके बाद ईरानी ने मातृत्व को एंटरप्रेन्योरशिप और निवेश से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अक्सर महिलाओं को 'बहुत ज़्यादा भावुक' कहकर कम आंका जाता है, जबकि यही भावनाएं उन्हें ज़्यादा मज़बूत और दृढ़ बनाती हैं। उन्होंने पूछा, 'क्या आप इसकी कोई आर्थिक कीमत तय कर सकती हैं?' इसके बाद उन्होंने कमरे में मौजूद कुछ भावुक महिलाओं की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि भावनाओं को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, खासकर जब बात बिज़नेस में महिलाओं की हो। उन्होंने कहा, 'लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यही भावना हमें ईमानदार बनाती है ताकि हम चुका सकें। यही भावना हमें कड़ी मेहनत करने, मज़बूती से आगे बढ़ने और तेज़ी से वापसी करने के लिए प्रेरित करती है।'

सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में सीबीआई की चार्जशीट

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाने वाले चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस खौफनाक साजिश के तार किसी और से नहीं, बल्कि अपनों से ही जुड़े निकले हैं। सीबीआई ने इस मामले में उसी कार्यालय के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जहां रथ काम करते थे। सीबीआई की विस्तृत जांच में यह बात सामने आई है कि चंद्रनाथ रथ को रास्ते से हटाने की साजिश रातों-रात नहीं बनी थी, बल्कि दिसंबर 2025 से ही उनकी हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था।

बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की निकली अंतिम यात्रा, हजारों लोगों ने दी भावभीनी विदाई

आर्यावर्त संवाददाता

नगरा (बलिया)। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा के दौरान उनके अनुज रमेश सिंह और पुत्र प्रिंस युकेश सिंह भावुक नजर आए। दोनों की आंखों से लगातार बहते आंसुओं ने उपस्थित लोगों को भी भावुक कर दिया।

वहीं, उमड़ी भीड़ उनके परिवार को यह भरोसा दिलाती रही कि पूरे क्षेत्र की जनता उनके साथ खड़ी है। विधायक की अंतिम यात्रा उनके खनवर स्थित आवास से शुरू होकर बछईपुर, सलेमपुर, चोगड़ा, कुकुरहा, हजौली, चिलकहर होते हुए बलिया शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए गंगा घाट स्थित अंतिम संस्कार स्थल

पहुंची।

पूरे मार्ग में आमजन, समर्थकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कई स्थानों पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर दिवंगत विधायक को अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात की समुचित व्यवस्था की थी। लोगों ने विधायक उमाशंकर सिंह के जनसेवा और सामाजिक कार्यों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान एवं धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ।

डीएम व एसपी ने दी श्रद्धांजलि

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शुक्रवार सुबह खनवर स्थित विधायक के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।

राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

खनवर में उपजिलाधिकारी रणधीर सिंह की मौजूदगी में पुलिस जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत विधायक को सलामी दी।

अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब

विधायक के अंतिम दर्शन के लिए गांव-गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महिलाओं ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई दी।

मां मरी धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर पहल तेज

आर्यावर्त संवाददाता

सुल्तानपुर/लंभुआ। विकासखंड लंभुआ क्षेत्र के साहपुर हरबंश स्थित प्रसिद्ध मां मरी धाम में गुरुवार को सेवार्थम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आशीष तिवारी ने विधि-विधान से मां मरी का पूजन-अर्चन किया। दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर के पुजारी एवं स्थानीय लोगों से धाम के धार्मिक महत्व की जानकारी ली और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं व समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।

निरीक्षण के दौरान डॉ. तिवारी ने मंदिर परिसर में स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, सार्वजनिक शौचालय, मंदिर की साज-सज्जा, प्रकाश व्यवस्था तथा महिलाओं द्वारा माता को कढ़ाई चढ़ाने के लिए समुचित स्थान की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर पुजारी से संवाद किया। इस दौरान संबंधित ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि बद्री प्रसाद यादव भी मौजूद रहे।चर्चा में सबसे बड़ी समस्या सार्वजनिक शौचालय के अभाव की सामने आई। इस पर डॉ. आशीष तिवारी ने तत्काल खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता से दूरभाष पर वार्ता कर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र शौचालय निर्माण कराने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कारणवश सरकारी स्तर पर शौचालय निर्माण में विलंब होता है, तो वह अपने निजी खर्च से भी शौचालय का निर्माण कराने के लिए तैयार हैं।बीडीओ नीलिमा गुप्ता ने इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बद्री प्रसाद यादव से बातचीत की। प्रधान प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।डॉ. आशीष तिवारी ने कहा कि मां मरी धाम में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है।

पेड़ों पर लटकते 'आशियाने' दे रहे प्रकृति का संदेश

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। कभी घर-आंगन में सुबह की पहली दस्तक गौरैया की चहचहाहट से होती थी। छप्पर, कच्ची दीवारों और खपरैल के नीचे तिनकों से बने छोटे-छोटे घोंसले इन नन्हे पक्षियों के बसेरे हुआ करते थे। लेकिन समय बदला तो इंसान के साथ रहने वाली गौरैया भी धीरे-धीरे मानव बस्तियों से दूर होती चली गई। बढ़ते कंक्रीट के जंगल, पेड़ों की घटती संख्या, ध्वनि प्रदूषण और पारंपरिक कच्चे मकानों के खत्म होने से इन पक्षियों के प्राकृतिक आशियाने लगातार कम हो रहे हैं।

इन परिस्थितियों के बीच पेड़ों की शाखाओं से लटकते बया पक्षी के घोंसले प्रकृति की अद्भुत कारीगरी का जीवंत नमूना दिखाई देते हैं। घास, तिनकों और रेशों को बेहद कुशलता से बुनकर तैयार किए गए ये घोंसले

देखने में जितने खूबसूरत हैं, उनकी बनावट उतनी ही वैज्ञानिक और सुरक्षित है। बया अपने घोंसले का प्रवेश द्वार नीचे की ओर रखता है, जिससे शिकारी आसानी से भीतर नहीं पहुंच पाते। इसके विपरीत गौरैया सामान्यतः घास, सूखे तिनकों, पंखों और रेशों से अपेक्षाकृत छोटे और सुरक्षित स्थानों पर घोंसला बनाती है। कच्चे घरों की छत, छप्पर, दीवारों की दरारें, बांस और पेड़ों की शाखाएं कभी इनके पसंदीदा ठिकाने हुआ करते थे। पक्षियों के ये घोंसले सिर्फ तिनकों की बुनावट नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन और जीव-जगत के सह-अस्तित्व का संदेश भी हैं। गौरैया की घटती मौजूदगी पर्यावरण के लिए चिंता का संकेत मानी जाती है। घरों के आसपास दाना-पानी रखना, देशी पेड़ लगाना और कृत्रिम घोंसले उपलब्ध कराना इन नन्हे पक्षियों के लिए फिर से सुरक्षित संसार तैयार करने की दिशा में छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

गोवंश ले जाने पर जब्त वाहन की नीलामी अवैध, हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 4 .75 लाख रुपये का मुआवजा देने का दिया आदेश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवंश वध निवारण अधिनियम के तहत एक वाहन को अवैध रूप से जब्त किए जाने के मामले में राज्य सरकार कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त कानूनी आधार के बिना वाहन को जब्त करना फिर उसकी नीलामी कर देना कानून के मुताबिक नहीं था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वाहन मालिक को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसका वाहनगोवंश को वध के लिए ले जाने को लेकर गलत आरोप में जब्त किया गया था। फिर उसकी नीलामी कर दी थी। अब न्यायमूर्ति संदीप जैन की

पीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर कि वाहन में गोवंश ले जाया जा रहा था, यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें वध के लिए ले जाया जा रहा था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रदेश के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से यह साबित नहीं हो सका कि गोवंश के उद्देश्य से वाहन राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था।ऐसे में वाहन की जब्ती और बाद की नीलामी पूरी तरह अवैध और मनमानी थी। सिर्फ शक और आशंका के आधार पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

इस फैसले को गोवंश परिवहन से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत के आदेश के मुताबिक गोवंश वध कानून के तहत कार्रवाई करते समय प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया और पर्याप्त साक्ष्यों का पालन करना होगा।

अदालत ने राज्य अधिकारियों को वाहन की जब्ती की तारीख (19 सितंबर, 2024) से उसकी वास्तविक रिहाई तक याचिकाकर्ता को 20,000 रुपये हर महाने की दर से मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।इसके अलावा मानसिक पीड़ा, वित्तीय कठिनाई और अनावश्यक उत्पीड़न के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा दिया गया है।आदेश की तारीख (5 अगस्त, 2026) तक मुआवजा लगभग 4।75 लाख बनता है, जो वाहन जारी होने तक बढ़ सकता है। अदालत ने सरकार को ये राशि मुआवजे के तौर पर याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो यह राशि उस अधिकारी से वसूल सकती है, जिसने इस मामले में कार्रवाई की थी।

पहले भी कोर्ट इस तरह के फैसले दे चुका है

इलाहाबाद हाईकोर्ट इससे पहले भी इस तरह के फैसले दे चुका है कि उत्तर प्रदेश के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए परमिट आवश्यक नहीं है। केवल संदेह या अनुमान के आधार पर वाहन जब्त नहीं किया जा सकता। अब यह साबित नहीं हो कि गोवंश को वध के लिए राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था, तो गोवंश वध निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया सोलर कर्मी, मौत

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। कोतवाली देहात क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव निवासी 25 वर्षीय विनय कुमार की शुक्रवार सुबह हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वह शहर के ओमनगर इलाके में सोलर पैनल लगाने का काम कर रहा था। हादसे के बाद गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे विनय ओमनगर में सोलर पैनल लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। तेज करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। विनय सोलर पैनल

लगाने का काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी और करीब तीन वर्षीय मासूम बेटी छोड़ गया है। परिवार में वृद्ध माता-पिता और दो भाई भी हैं। हादसे के बाद हाईटेंशन बिजली लाइनों के आसपास काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बिजली लाइनों के आसपास निर्माण या सोलर पैनल लगाने जैसे कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए, जिससे इस तरह के दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति न हो।

कोख में पल रही जिंदगी का खौफनाक अंत!

अलीगढ़ में 8.5 महीने के गर्भपात मामले में डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत और कानून दोनों को शर्मसार कर दिया है। गौंडा थाना क्षेत्र में साढ़े आठ माह की गर्भवती नाबालिग युवती का कथित रूप से अवैध तरीके से गर्भपात कराने और शिशु के शव को नहर किनारे दफनाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल के संचालक व डॉक्टर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामला अलीगढ़ के गौंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, गांव के ही एक युवक के साथ संपर्क में आने से नाबालिग युवती गर्भवती हो गई थी। जब गर्भ करीब साढ़े आठ महीने का हो गया, तो परिवार में सामाजिक बदनामी का डर सताने लगा। आरोप है कि युवती के परिजनों ने इगलास स्थित एक निजी अस्पताल से संपर्क किया और कानून को ताक पर रखकर कथित रूप से अवैध तरीके से प्रसव/गर्भपात कराया।

वारदात को छिपाने की नीयत से आरोपियों ने नवजात शिशु के शव को नहर किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया। हालांकि, मामले की भनक लगते ही पीआरवी के माध्यम से पुलिस को सूचना मिल गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी (CO) इगलास कमलेश कुमार ने स्वयं जांच की कमान संभाली और थाना गौंडा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

शव निकालते समय भावुक हुए पुलिसकर्मी

पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ नहर किनारे दबिश देकर दफनाए गए मासूम के शव को बाहर निकलवाया और जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब साढ़े आठ माह के मासूम का शव बाहर निकाला गया, तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी स्तब्ध और भावुक हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

फर्जी अस्पताल और डॉक्टरों पर गिरा कानून का चाबुक

जांच में इगलास के निजी अस्पताल की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध पाई गई। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अब अस्पताल के पंजीकरण और उसकी वैधता की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से अस्पताल चलाने और जानलेवा कृत्य में शामिल होने के लिए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।

पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज, 4 आरोपी सलाखों के पीछे

पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट और आईपीसी/बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी संतोषी, सचिन, अस्पताल संचालक ईशान और डॉक्टर भावना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले की विस्तृत विवेचना जारी है।

भैंस ने एक साथ दिए दो पड़वे, देखने के लिए उमड़ी भीड़

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के कनकपुर सिकवा गांव में उस समय कौतूहल का माहौल बन गया, जब एक भैंस ने एक साथ दो पड़वों को जन्म दिया। गांव निवासी त्रिभवन सरोज पुत्र राम केवल सरोज की भैंस ने चार अगस्त को दो पड़वों को जन्म दिया। एक साथ दो पड़वों के जन्म की खबर गांव में फैलते ही उन्हें देखने के लिए ग्रामीणों और आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी। बताया जा रहा है कि भैंस और उसके दोनों नवजात पड़वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। दोनों पड़वे अपनी मां के साथ सामान्य रूप से हैं और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। पशुपालक त्रिभवन सरोज ने बताया कि प्रसव के बाद भैंस भी स्वस्थ है और सामान्य रूप से दूध दे रही है। एक साथ दो पड़वों को देखकर परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं। त्रिभवन सरोज ने इसे अपने लिए सौभाग्य की बात बताते हुए कहा कि उनके घर में एक साथ दो पड़वों का जन्म होना खुशी का अवसर है। इधर गांव में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसे भी एक भैंस के दो पड़वे पैदा होने की जानकारी मिल रही है।

शिव दानव-मानव, भूत-पिशाच सबके 'विश्वनाथ'... कांवड़ यात्रा यानी समावेशी समाज का नव-जागरण

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। भगवान शिव को जलार्पण का अभीष्ट लेकर निकले कांवड़ियों के समूह को आंखें बंद कर आत्मसात कीजिए। श्रद्धा-आस्था की वह धारा दिखेगी जो प्रयागराज के महाकुंभ में दिखाई देती है, अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर परिसर में दिखाई देती है, बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में नजर आती है और काशी विश्वनाथ कारिडोर में दिखाई देती है। हिंदू समाज की आंतरिक समरसता, सर्वसमावेशिता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्भुत दृश्य वर्तमान में कांवड़ मार्गों पर सजीव है।

सदियों पुरानी सामाजिक सीमाएं और असमानताएं आस्था के पावन जल में विसर्जित हो चुकी हैं। कांवड़ियों की भीड़ में कोई ब्राह्मण है, कोई दलित, कोई ओबीसी तो कोई आदिवासी। कंधे पर बंधी कांवड़ किसी की जाति नहीं पूछती। रास्ते के भंडारे किसी की कुल-गोत्र जांच के बाद प्रसाद नहीं बांटते। यह कांवड़ यात्रा के रूप में भारत के सामाजिक

अवचेतन का एक जीवंत मानचित्र है और उत्तर प्रदेश इसका प्रतिनिधि राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह राज्य समावेशी हिंदू समाज के नव-जागरण का प्रतीक हो चला है।

हिंदुत्व की सामाजिक-सांस्कृतिक व्याख्या करने वाले विचारक कांवड़ यात्रा को हिंदू समाज की भीतरी समावेशिता के प्रमाण के रूप में देखते हैं और इसका आधार यात्रा में दलितों और पिछड़ों की बढ़ती भागीदारी है। संस्कृतिकरण और सांस्कृतिक वर्चस्व की धारणाओं को यह यात्रा व्यवहार के धरातल पर एक नई व्याख्या प्रदान करती है। यह यात्रा सिद्ध करती है कि सनातन संस्कृति में ईश्वर की भक्ति हर उस आत्मा का सहज अधिकार है जो शिवत्व में विलीन होना चाहती है।

दलित और पिछड़ा वर्ग, जो पूर्व में कई सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों से वंचित रहा, आज इस यात्रा की रीढ़ है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि योगी सरकार ने उन्हें समावेशी सम्मान का हकदार माना है। सनातन परंपरा के प्रति उनका अटूट विश्वास और अपने सांस्कृतिक अधिकारों पर उनके सहज दावे की स्वीकृति का यह बड़ा धरातल है। यह इस पूर्वाग्रह को खारिज करता है कि भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक उच्च जातियों के वर्चस्व को बनाए रखने के साधन रहे हैं।

> शिव तो देव, दानव, मानव, भूत, पिशाच, सबके 'विश्वनाथ' और 'भोलेनाथ' हैं। शिव विष को अपने कंठ में धारण कर जगत की रक्षा करते हैं और औघड़दानी बनकर अपने हर भक्त पर समान रूप से अनुकंपा बरसाते हैं। कांवड़ मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति 'भोले का भक्त' है। वहां उसकी कोई सामाजिक, आर्थिक या जातीय पहचान नहीं रह जाती। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो सामाजिक असमानता की दीवारें अपने आप ढहने लगती हैं।
>
> **आचार्य डॉ. विक्रमादित्य (पीतांबरा पीठाधीश)**

संत कबीर, संत रविदास ने जो समता की अलख जगाई...

जब लाखों की संख्या में वंचित और पिछड़े वर्ग के युवा शिवभक्ति के इस महायज्ञ का मुख्य ध्वजवाहक बनते हैं, तो वे सिद्ध करते हैं कि सनातन धर्म का वास्तविक ढांचा वर्चस्व पर नहीं, बल्कि सहअस्तित्व और भ्रातृत्व पर आधारित है। भक्ति आंदोलन के दौर में संत कबीर, संत रविदास, संत चोखामेला और संत कनकदास ने जिस आध्यात्मिक समता की अलख जगाई थी, वही अलख आज कांवड़ यात्रा के रूप में सड़कों पर साकार होती दिखाई देती है और समाज के अंतिम व्यक्ति के भीतर स्वाभिमान, गौरव और एकता की अनुभूति जाग्रत करती है।

हम इसे सनातन समाज के वास्तविक ऐश्वर्य की संज्ञा दे सकते हैं जो प्रशासनिक इच्छाशक्ति, राज्य का संरक्षण और एक अनुकूल वातावरण से संभव होता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कांवड़ यात्रा को भव्य, सुरक्षित और गौरवमयी 'सांस्कृतिक उत्सव' का रूप दिया है तो यह ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है। अब से दस साल पहले की बात करें तो राज्य के स्तर पर कांवड़ यात्रा को उपेक्षा, प्रशासनिक बाधाओं, सुरक्षा के खतरों और संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। योगी सरकार ने इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदला है। सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि आस्था का सम्मान करना और प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक परंपराओं को सुरक्षित व सम्मानजनक वातावरण में जीने का अवसर देना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। कांवड़ मार्गों पर पुष्पवर्षा का जो दृश्य पिछले कुछ वर्षों में उभरा है, वह राज्य द्वारा अपने नागरिकों की आस्था को दिया गया बड़ा सम्मान है। जब हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, तो यह दृश्य पूरे समाज के मन में एक नया आत्मविश्वास और गौरव भर देता है।

अध्यात्म सामाजिक सशक्तीकरण और समरसता का माध्यम

कांवड़ यात्रा के सुचारु संचालन के लिए की गई व्यापक व्यवस्थाएं, जैसे सुरक्षित और स्वच्छ मार्ग, चिकित्सा शिविर, विश्राम स्थल, प्रकाश व्यवस्था, और कांवड़ियों के भोजन-पानी के लिए उचित प्रबंध यह दर्शाते हैं कि योगी सरकार अध्यात्म को सामाजिक सशक्तीकरण और समरसता का माध्यम मानती है। कांवड़ मार्गों पर लगने वाले सेवा शिविरों में जो सेवा भावना दिखाई देती है, वह समाज के भीतर से छुआछूत, ऊंच-नीच और वैमनस्य के भाव को जड़ से समाप्त कर देती है। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए आर्थिक या राजनीतिक प्रयास तब तक पर्याप्त नहीं होते, जब तक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल पर बराबरी का अहसास न हो। कांवड़ यात्रा इसी आध्यात्मिक समता का व्यावहारिक मंच है। योगी सरकार ने इस मंच को जो भव्यता, सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया है, उससे समाज के शोषित और वंचित वर्गों के भीतर सनातन धर्म के प्रति नया स्वाभिमान पैदा हुआ है।

विविधता में एकता और समरसता का अद्भुत दर्शन

कांवड़ यात्रा का यह विहंगम स्वरूप भारत की उस आंतरिक शक्ति का दर्शन कराता है जो विविधता में एकता और समरसता में ही अपना प्राण देखती है। यह यात्रा उन ताकतों को भी जवाब है जो समाज को जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती हैं। संस्कृतिकरण की यह धारा समस्त हिंदू समाज के एक साथ मिलकर उठ खड़े होने का पर्याय है। यह सनातन समाज को उसकी वास्तविक पहचान 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सर्वे भवंतु सुखिनः' की ओर ले जा रही है।

सपा पर बरसे योगी: परिवारवाद, दंगे और पेपर लीक को लेकर साधा निशाना, गोविंद साहब मेला राजकीय मेला घोषित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। अंबेडकरनगर के गोविंद साहब में शुक्रवार को आयोजित जनसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद, कानून व्यवस्था, सरकारी भर्तियों और दंगों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में योग्यता के बजाय भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी था, जबकि वर्तमान सरकार विकास, रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा पिछड़ों और युवाओं की बात करती है, लेकिन उसके शासनकाल में उनके हितों की अनदेखी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता नहीं थी और प्रश्नपत्र खरीदने, घर ले जाकर परीक्षा

लिखने तथा गांव-गांव नौकरी बेचने जैसी शिकायतें सामने आती थीं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार अब तक नौ लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरी दे चुकी है।

अब माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

योगी ने कहा कि सपा शासन में बालू, भूमि, वन और पशु माफिया सक्रिय थे। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। सपा के झंडे के सहारे अवैध वसूली और दबंगई होती थी। इससे व्यापारी भय के माहौल में रहते थे। अब सरकार माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ और कानपुर में हुए दंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि अब प्रदेश की पहचान 'नो कर्फ्यू, नो दंगा' के रूप में बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिली है। इससे किसानों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए महाराजा सुहेलदेव, वीरांगना ऊदा देवी, रानी दुर्गावती, अवंतीबाई लोधी, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, डॉ. भीमराव आंबेडकर, छत्रपति साहूजी महाराज और ज्योतिबा फुले से जुड़े स्थलों के विकास का उल्लेख किया।

धरोहरों को सम्मान दिलाने का कार्य जारी

योगी ने आरोप लगाया कि अयोध्या को सम्मान मिलना, सपा और कांग्रेस को पसंद नहीं है। सपा सरकार में रामभक्तों पर गोलियां चलीं और कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जबकि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। ऐतिहासिक धरोहरों को सम्मान दिलाने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए निशुल्क राशन, आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के इलाज, निराश्रित महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जानकारी दी। गांवों में सड़क, बिजली और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

स्किलिंग और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीउन्होंने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और प्रत्येक जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर अपॉर्च्युनिटी जोन विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया। इन केंद्रों पर युवाओं को स्किलिंग और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले कोई मुख्यमंत्री गोविंद साहब नहीं आया। नोएडा जाने से जुड़ी पुरानी राजनीतिक मान्यता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुर्सी चली जाए तो भी जनता के बीच जाना जरूरी है। हमारी सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण और बिना भेदभाव सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

गोविंद साहब मेला राजकीय मेला घोषित

मंच से संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गोविंद साहब मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाला गोविंद साहब मेला राजकीय मेले के रूप में आयोजित होगा। घोषणा होते ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने खुशी जताई। बताते चलें कि गोविंद साहब का मेला लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रहा है। राजकीय मेला घोषित होने के बाद इसके आयोजन और व्यवस्थाओं को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। इस घोषणा से मेले के विकास और सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुलने की संभावना है।

अखिलेश यादव की दिनचर्या पर भी कसा तंज

जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दोपहर 12 बजे उठते हैं, दो बजे तैयार होते हैं और फिर अपने चाचा से चर्चा के बाद ट्वीट करते हैं। इसके बाद जिम जाने और महफिल जमाने में समय बीत जाता है। जो लोग खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, वे प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कैसे संभालेंगे। उन्होंने इसे सपा के नेतृत्व और कार्यशैली पर सवाल बताते हुए प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने में विपक्ष की विफलता का आरोप लगाया।

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने दिया इस्तीफा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉ. रामाशीष राय ने अपने पद के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह को संबोधित पत्र भेजकर अपने निर्णय की जानकारी दी है।अपने इस्तीफे में डॉ. राय ने राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के लिए जयंत सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों का व्यापक दौरा किया, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया तथा संगठन के विस्तार और सशक्तीकरण के लिए लगातार कार्य किया।डॉ. राय ने अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि वह वर्ष 1974-75 के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से प्रेरित होकर राजनीति में आए थे। उनके अनुसार उस आंदोलन का उद्देश्य भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित करना था, लेकिन आज भी वे लक्ष्य अधूरे प्रतीत होते हैं।उन्होंने अपने पत्र में कहा कि भारतीय लोकतंत्र पर धनबल और प्रभावशाली वर्गों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उनके अनुसार समाज को जाति, उपजाति और संप्रदाय के आधार पर विभाजित करने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। उन्होंने यह भी लिखा कि किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि नौजवान बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहा है।डॉ. राय ने कहा कि देश के महापुरुषों ने सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया था।

पीसीएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से मिले अखिलेश यादव, अतिरिक्त अवसर देने की मांग का किया समर्थन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पीसीएस, आरओ/एआरओ तथा बीईओ परीक्षा की तैयारी कर रहे उन अभ्यर्थियों से मुलाकात की, जो कोरोना काल, पाठ्यक्रम में बदलाव और नई सेवा भर्ती नियमावली के कारण आयु सीमा पार कर चुके हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर प्रतियोगी परीक्षाओं में अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग उठाई।

अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। इसके बाद वर्ष 2023 से 2025 के दौरान पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव किए गए, जिससे उन्हें नई व्यवस्था के अनुसार दोबारा तैयारी करनी पड़ी। उनका कहना था कि नई सेवा भर्ती नियमावली-2026 लागू होने के बावजूद आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।अभ्यर्थियों ने मांग की कि परिस्थितियों को देखते हुए पीसीएस परीक्षा में दो अतिरिक्त अवसर तथा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) और खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती परीक्षा में एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए, ताकि वर्षों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।इस अवसर पर अखिलेश यादव ने अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल, पाठ्यक्रम में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया में हुए परिवर्तनों का असर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों पर पड़ा है।अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं के संघर्ष के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इन अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।अभ्यर्थियों ने भी सरकार से मांग की कि उनके वर्षों के परिश्रम, बदली हुई परिस्थितियों और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी योग्यता के आधार पर भाग ले सकें।

लखनऊ–सीतापुर हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, चालक की जलकर मौत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी के बीकेटी थाना क्षेत्र में लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में कार में आग लगने से चालक की जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, 6 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि सरैया बाजार स्थित वीरेंद्र धर्मकांटा के पास मारुति कार (संख्या यूपी-32-सीएस-0626) में अचानक आग लग गई है। सूचना पर बीकेटी थाना पुलिस तथा अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुकी थी। आग बुझने के बाद वाहन की चालक सीट पर एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। ई-चालान एप के माध्यम से वाहन के स्वामी की पहचान अलमास हक (32 वर्ष) के रूप में हुई। वह विकासनगर क्षेत्र के साकेत विहार कॉलोनी, खुर्रम नगर के निवासी बताए गए हैं।पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए तथा परिजनों को घटना की सूचना दे दी। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों तथा यदि कोई तहरीर प्राप्त होती है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के नाका हिण्डोला थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा बाद में विवाह से इनकार कर जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मामले की विवेचना जारी है।पुलिस के अनुसार, पीड़िता की तहरीर पर थाना नाका हिण्डोला में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी अखिलेश मिश्रा ने उससे विवाह का वादा कर विश्वास में लिया और इसी आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह की बात कही तो आरोपी ने उससे दूरी बना ली। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज की गई तथा जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद थाना नाका हिण्डोला पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को पानदरीबा स्थित शिओना होटल में दबिश देकर आरोपी अखिलेश मिश्रा (40 वर्ष) निवासी शहनशापुर जक्खिनी, थाना राजातालाब, जनपद वाराणसी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की विवेचना अभी जारी है। पीड़िता के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों तथा अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच के दौरान अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं तो उन्हें भी विवेचना में शामिल किया जाएगा।पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

ठाकुरगंज में सांड की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बंद पड़ी धान मिल में सांड की गला काटकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो चाकू, एक चापड़ और तीन बोरियां भी बरामद की हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में शस्त्र अधिनियम की धारा भी बढ़ाई गई है।पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त को न्यू हैदरगंज स्थित एक बंद पड़ी धान मिल में सांड का गला काटकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर ठाकुरगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक तथा फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से आवश्यक भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए। घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। पशु चिकित्सक की जांच के बाद नियमानुसार सांड के शव को घटनास्थल के निकट सम्मानपूर्वक दफनाया गया।

जिम में हुए विवाद का लिया बदला, जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने जान से मारने की नीयत से किए गए हमले के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि जिम में हुए विवाद का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।पुलिस आयुक्त तरुण गाबा तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) मोहम्मद मुश्ताक के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त को शक्ति सिंह निवासी ओमैक्स आर-2, अर्जुनगंज, सरसवां ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में तहरीर देकर बताया था कि 30 जुलाई को उनके भाई मार्केश सिंह के साथ कुछ लोगों ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और लोहे की रॉड तथा ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया।

जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 6 अगस्त को मुख्य आरोपी दीपांशु यादव (24 वर्ष) निवासी ग्राम शाहखेड़ा, थाना सुशांत गोल्फ सिटी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि सूर्या जिम में व्यायाम के दौरान उसकी मार्केश सिंह से कहासुनी और विवाद हो गया था। इसी विवाद का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया।पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की विवेचना जारी है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

रामकृष्ण पार्क व्यापार मंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

नई कार्यकारिणी ने संभाली जिम्मेदारी, व्यापारियों की एकजुटता और हितों की रक्षा का लिया संकल्प

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। अमीनाबाद स्थित बुद्धूलाल धर्मशाला में रामकृष्ण पार्क व्यापार मंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर व्यापारियों ने संगठन की मजबूती, एकजुटता तथा व्यापारिक हितों की रक्षा का संकल्प लिया।समारोह के मुख्य अतिथि लखनऊ व्यापार मंडल के चेयरमैन राजेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र तथा वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा रहे। कार्यक्रम में संरक्षक विनोद अग्रवाल एवं केदारनाथ बाजपेयी भी मंचासीन रहे।मुख्य अतिथि अमरनाथ मिश्र ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वालों में अध्यक्ष मनीष वर्मा, महामंत्री हर्ष कनोडिया, कोषाध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार अनेजा, अनुज अग्रवाल, कपिल बग्गा एवं मनोज गर्ग, उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता, मनोज रतनानी, सुरेश अग्रवाल, योगेश गुप्ता, मोहित गुप्ता, हरजीत सिंह, अर्पण सेठ एवं आबिद अली, वरिष्ठ मंत्री दीपक दुलानी, दीपक खुराना, नवीन कसेरा एवं चंदन रस्तोगी, मंत्री आशीष गुप्ता, सचिन गुलाटी, रोहित रस्तोगी, अमित बालाजी, मिक्की गुलाटी, राजू मिश्रा एवं मनीष तुल्सीयान, संगठन मंत्री विवेक टोकी एवं अतुल अरोड़ा, प्रचार मंत्री नीवन सोनी तथा कार्यकारिणी सदस्य शारिक, आर.के. मिश्रा, रजत अग्रवाल, यश भटेजा एवं अर्जुन सिंह शामिल रहे।मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि संगठित व्यापारी समाज ही अपनी समस्याओं का प्रभावी समाधान कराने में सक्षम होता है। उन्होंने सभी व्यापारियों से संगठन को मजबूत बनाने और आपसी एकता बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि व्यापारियों की आवाज तभी प्रभावी होती है जब वे एक मंच पर संगठित होकर अपनी बात रखें।लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि व्यापारिक संगठनों की मजबूती ही व्यापारियों के अधिकारों की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रामकृष्ण पार्क व्यापार मंडल की नवगठित टीम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ व्यापारियों की समस्याओं के समाधान, बाजार की व्यवस्थाओं में सुधार तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का कार्य करेगी।उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल केवल व्यापारियों की समस्याओं को उठाने का मंच नहीं है, बल्कि सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी सदैव अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। व्यापारी समाज प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए व्यापारियों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा।अमरनाथ मिश्र ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई टीम संगठन की गरिमा को बनाए रखते हुए व्यापारियों के हितों की रक्षा, आपसी समन्वय तथा सेवा भावना के साथ कार्य करेगी और प्रत्येक व्यापारी की आवाज को मजबूती से प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी।वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने कहा कि संगठित व्यापारी समाज ही अपनी समस्याओं का प्रभावी समाधान कराने में सक्षम होता है। लखनऊ व्यापार मंडल हमेशा व्यापारियों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा बाजारों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।व्यापारी नेता जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि रामकृष्ण पार्क व्यापार मंडल की नवगठित टीम पूरी ऊर्जा, पारदर्शिता और सेवा भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ व्यापार मंडल हर कदम पर संगठन के साथ खड़ा रहेगा तथा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए संगठन भविष्य में भी मजबूती से कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष केदारनाथ बाजपेयी ने किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल बजाज ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए सफल कार्यकाल की कामना की।समारोह के अंत में सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया। उपस्थित व्यापारियों ने नवगठित कार्यकारिणी का जोरदार स्वागत करते हुए सफल एवं जनहितकारी कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर मुमताज मार्केट के महामंत्री प्रियंक गुप्ता, अध्यक्ष यूसुफ, महामंत्री रिजवान, कार्यवाहक अध्यक्ष आनंद गुलाटी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

लखनऊ से हुई देश की पहली महिला पेशेवर वॉलीबॉल लीग की शुरुआत

लखनऊ। भारतीय खेल जगत में महिला वॉलीबॉल को नई पहचान और पेशेवर मंच देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी आधारित महिला पेशेवर वॉलीबॉल लीग की आधिकारिक शुरुआत शुक्रवार को लखनऊ में की गई। इस लीग का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को दीर्घकालिक पेशेवर अवसर उपलब्ध कराना, खेल में निजी निवेश को बढ़ावा देना तथा देश में महिला वॉलीबॉल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।लीग के आधिकारिक अनावरण समारोह का आयोजन लखनऊ के द सेंट्रम में 'राइजिंग क्वीन ऑफ द कोर्ट' विषय के साथ किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह तथा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान सहित अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, खेल प्रशासक, उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि और खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

मिलावटखोरों के खिलाफ भी करना पड़ेगा देशव्यापी आंदोलन

संसद भवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार जारी है और वहीं देश के तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर भी मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें भी लगातार निकल कर सामने आ रही है, जिसपर बड़े पैमाने पर चर्चा, वाद-संवाद और कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश के सभी लोगों के जीवन से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने का समय किसी के पास नहीं है। सत्ता में बैठने वाली किसी भी सरकार (चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो) के पास इसके समाधान का कोई स्थायी फॉर्मूला या विज़न नहीं है, विपक्ष के पास भी इस पर बात करने की फुर्सत नहीं है और सरकारी अधिकारी अपने में ही मस्त है।

मिलावटखोरी की समस्या अब हमारे देश की सबसे बड़ी भयावह समस्या बनती जा रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए अब बड़े स्तर पर कदम उठाए बिना कोई बात नहीं बनेगी। देश में कानून भी है, नियम भी है, निगरानी के लिए विभाग भी है और अधिकारी भी है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मिलावटखोरों को किसी भी बात का कोई डर ही नहीं है।

हाल ही में देश के एक बड़े अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में जो दावा किया है, उसने सबकी नींदे उड़ा दी है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश की कई आटा मिलों में गेंहू के आटे में सफेद पत्थर का चूरा यानी स्टोन पाउडर मिलाया जा रहा है। मुनाफाखोरी के लालच में ये मिलावटखोर हमें पत्थर वाले आटे से बनी रोटी खाने को मजबूर कर रहे हैं। जबकि ये भी जानते हैं कि इस मिलावटी आटे से बनी रोटी को खाने से लोगों के शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेंगे।

आजकल लोगों के घरों से लेकर, फ़ास्ट फ़ूड, शादी-ब्याह और पार्टियों तक में सबसे ज्यादा पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। कई एक्सपर्ट/ जिम ट्रेनर तो बॉडी को मजबूत बनाने के लिए भी पनीर खाने की सलाह देते हैं। लेकिन पनीर में मैदा या अरारोट मिलाना और स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं वनस्पति तेल का इस्तेमाल कर सिंथेटिक या नकली पनीर बनाना तो आम बात हो गई है। बल्कि ऐसे गंभीर मामले भी कई बार सामने आए हैं, कि डिटर्जेंट या यूरिया से बने दूध का भी इस्तेमाल कर पनीर बनाया और बेचा जाता है।

महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही, राज्य में एनालॉग पनीर यानी नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि असली पनीर बताकर इसे बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह करना है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने आदेश में सख्त शब्दों में कहा कि नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार भी एनालॉग पनीर यानी नॉन डेयरी पनीर को लेकर ऐसा ही फैसला कर चुकी है।

सबसे अधिक दुःखद और परेशानी में डालने वाला तथ्य तो यह है कि देश की नामी-गिरामी कंपनियां भी उपभोक्ताओं को धोखा देने का कोई मौका नहीं चूकती है। रोजमर्रा की जरूरत का कई सामान बेचने वाली एफएमसीजी कंपनी डाबर को लेकर भी चौंकाने वाली ख़बर सामने आई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डाबर द्वारा किए जा रहे ' 100% प्योर', '100% ऑर्गेनिक' और '100% नेचुरल' जैसे दावों को भ्रामक बताते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री को तुरंत रोकने का आदेश दे दिया है। इन प्रोडक्ट्स में शहद, गाय का देसी घी, तिल का तेल और नारियल पानी जैसी कई चीजें शामिल हैं। डाबर को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी जमा करने को कहा गया है।

इससे पहले भी कई नामी-गिरामी और बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि यही कंपनियां जब विदेश खासकर अमेरिका या यूरोपीय देशों में कोई सामान बेचती है तो उसकी क्वालिटी का खास ध्यान रखती है लेकिन भारतीयों के लिए इनका एटीट्यूड 'सब चलता है टाइप' ही होता है। लोग पैसे खर्च करने को तैयार हैं ताकि उन्हें शुद्ध आटा, दाल, चावल, मसाले, चीनी, दूध, घी, खाद्य तेल, सब्जियां, पनीर, शहद, पानी और अन्य सामान मिल सके। लेकिन ज्यादा खर्च के बाद भी उनके साथ न केवल ठगी की जा रही है बल्कि लोग गंभीर बीमारियों के भी शिकार होकर मरते भी जा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देने से इस भयावह समस्या का समाधान हो जाएगा, कतई नहीं। इसके लिए युद्धस्तर पर एक मिशन के तहत कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ेगा। नकली सामानों को बनने के स्तर पर ही रोकना होगा, इसके लिए उत्तरदायी विभाग में मैन पावर बढ़ाने के साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। इससे जुड़े विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को हर महीने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी ऑनलाइन भरना चाहिए।

नवजात का पहला सुरक्षा कवच- स्तनपान और इसका सामाजिक महत्व

हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य माताओं और समाज को शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना है।

धनंजय राठौर

विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु के स्वास्थ्य के लिए माँ के दूध के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना और शुरुआती छह महीने तक केवल माँ का दूध ही देना बच्चे के लिए सबसे जरूरी है। स्तनपान के दौरान त्वचा से त्वचा का संपर्क मां और बच्चे के बीच भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है, जिससे आराम, गर्माहट और सुरक्षा की भावना मिलती है जो स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक होती है।

हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य माताओं और समाज को शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार, शिशु के जन्म के बाद पहला घंटा और शुरुआती छह महीने उसका पूरा जीवन संवारने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। स्तनपान करने वाले शिशुओं में दस्त, निमोनिया, कान के संक्रमण और कुछ श्वसन संबंधी संक्रमण जैसी आम बचपन की बीमारियों का खतरा कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इष्टतम स्तनपान शिशुओं को जानलेवा संक्रमणों से बचाकर विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लाखों शिशु मृत्यु को रोकने की क्षमता रखता है।

जन्म के पहले कुछ घंटों में, माँ का दूध सिफ़र् भोजन नहीं होता, बल्कि यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा की पहली खुराक होती है, जो सीधे माँ के शरीर से बच्चे तक पहुँचती है। जन्म के बाद का पहला घंटा, जिसे अक्सर गोल्डन आवर कहा जाता है, स्तनपान शुरू करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बच्चे स्वाभाविक रूप से सतर्क रहते हैं और सहज रूप से स्तन की तलाश करते हैं। त्वचा से त्वचा का शुरुआती संपर्क न केवल सफल स्तनपान की दर को बढ़ाता है, बल्कि बच्चे के तापमान, हृदय गति और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

शिशु के जन्म के तुरंत बाद (एक घंटे के भीतर) मां का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका होता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज, प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं और उसे विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं।

चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की स्पष्ट सलाह है कि जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक बच्चे को केवल मां का दूध ही देना चाहिए। इस अवधि के दौरान बच्चे को पानी, ऊपर का दूध या शहद जैसी चीजें देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मां के दूध में बच्चे की प्यास और भूख बुझाने के लिए सही अनुपात में पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। 6 महीने पूरे होने के बाद, स्तनपान जारी रखते हुए बच्चे को धीरे-धीरे ऊपरी पौष्टिक आहार देना शुरू किया जा सकता है, जिसे 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है।

शिशु के लिए स्वास्थ्य वरदान है, स्तनपान कराने से बच्चों में दस्त, निमोनिया, कान के संक्रमण और कुपोषण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि स्तनपान करने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य अन्य बच्चों की तुलना में बेहतर होता है। यह आगे चलकर बच्चों में मोटापा, डायबिटीज और अस्थामा जैसी क्रोनिक बीमारियों की संभावना को घटाता है।

स्तनपान कराने से माताओं में स्तन कैंसर और अंडाशय के कैंसर का जोखिम कम होता है। यह प्रसव के बाद वजन घटाने और गर्भाशय को पुनः सामान्य आकार में लाने में मदद करता है। मां और बच्चे के बीच एक भावनात्मक और अटूट संबंध स्थापित होता है।

स्तनपान केवल एक मां की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज की साझी जिम्मेदारी है। अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव, सामाजिक रूढ़ियों, या कामकाजी माहौल में सुविधाओं की कमी के कारण महिलाएं समय पर स्तनपान नहीं करा पातीं। प्रसव के बाद मां को सही पोषण, मानसिक शांति और आराम मिलना आवश्यक है ताकि वह बिना किसी तनाव के बच्चे को स्तनपान करा सके। कामकाजी माताओं के लिए कार्यस्थलों में क्रैच सुविधा, मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) और ब्रेस्टफीडिंग ब्रेक जैसी सुविधाएं होना बेहद जरूरी है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर माताओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ फीडिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए।

विश्व स्तनपान सप्ताह हमें यह याद दिलाता है कि बच्चों को उनका मौलिक अधिकार मां का दूध दिलाने के लिए हम सभी को मिलकर एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। जब एक मां बिना किसी संकोच और बाधा के अपने बच्चे को स्तनपान करा सकेगी, तभी हम एक कुपोषण-मुक्त और स्वस्थ समाज की कल्पना साकार कर सकते हैं।

लेखक संयुक्त संचालक, जनसंपक हैं

व्यंग्य

नागरिक अधिकारों की अनदेखी

पुलिस कार्रवाइयों में मानव अधिकारों की अनदेखी बढ़ती चली गई है। गाहे-ब-गाहे ऐसी धारणा बनी है कि पुलिसकर्मी सरकारी नीति के तहत या सत्ताधारी नेताओं के निर्देश पर नागरिक अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व ने परीक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों की जवाबदेही तय करने के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन उसी आंदोलन के दौरान ही पुलिस जवाबदेही का जो सवाल खड़ा हुआ, उसे उठाने की जिम्मेदारी उसने नहीं निभाई। यह स्वागतयोग्य है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये दायित्व उठाया है। इससे संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का नया मुद्दा भी उभरा है। गांधी ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में दो ठोस सवाल पूछेः क्या 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान उन पर पैलेट गन सहित जानलेवा ताकत के इस्तेमाल की मंजूरी आपने दी और अगर नहीं, तो फिर किसने दी? सादी पोशाक में जो लोग लाठियों से छात्रों को पीटते देखे गए, वे पुलिसकर्मी थे या स्वयंसेवक, और उनकी तैनाती का आदेश किसने दिया?

देश के जनमत का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी की इस टिप्पणी से सहमत होगा कि ऐसी हिंसा से हर कायदा नष्ट होता है और इस घटना ने देशवासियों में आक्रोश भरा है। आशा है, गृह मंत्री नेता विपक्ष को जवाबी पत्र लिखने अथवा संसद में इन प्रश्नों का उत्तर देने की अपनी जवाबदेही स्वीकार करेंगे। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि हाल के वर्षों में पुलिस कार्रवाइयों के दौरान मानव अधिकारों के प्रति सम्मान का भाव लगातार घटता चला गया है। गाहे-ब-गाहे ऐसी धारणा बनी है कि पुलिसकर्मी सरकारी नीति के तहत या उच्च पदस्थ राजनेताओं के निर्देश पर नागरिक अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं।

20 जुलाई को पुलिसकर्मियों ने देश की राजधानी में, विश्व मीडिया के सामने, उच्च-मध्यम एवं मध्य वर्ग से आए ज़ेन-जी प्रदर्शनकारियों पर वैसी ही अमान्य कार्रवाइयां कीं। चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है, इसलिए यह अपेक्षित है कि अमित शाह इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें। अगर पुलिसकर्मियों ने खुद अति-उत्साह दिखाया, तो उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। अगर निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया गया, तो गृह मंत्री को अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। जवाबदेही का सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म नहीं हो गया है।

ब्लॉग

अब शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग क्यों नहीं मिलते?

प्रोफ़ेसर (डॉ.) डी. के. पांडेय

आज के एक-दूसरे पर निर्भर समाज में युवाओं, खासकर जेनरेशन जेड (जेन ज़ी) का व्यवहार समाज के लिए बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्हें अक्सर बेसब्री, बिना सोचे-समझे सोचने की आदत और कुछ मामलों में, बुरे बर्ताव वाला माना जाता है। यह सोच, हालांकि आम हो सकती है, और हर व्यक्ति में अलग-अलग भी हो सकती है। लेकिन यह इसके अंदरूनी कारणों और समाज की संभावित प्रतिक्रियाओं की एक ज़रूरी जांच को बढ़ावा देती है। इन उभरते हुए पैटर्न को समझने के लिए एक बहुआयामी नज़रिए की ज़रूरत है, जिसमें टेक्नोलॉजी में तरक्की, पढ़ाई के बदलते तरीकों, पेरेंटिंग स्टाइल में बदलाव और बड़े सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल के गहरे असर को माना जाए। यह आवश्यक है कि जेन ज़ी में इन आदतों के पीछे के संभावित कारणों पर गहराई से चर्चा हो, जिसमें डिजिटल इमर्शन, तुरंत मिलने वाले फ़ायदे का असर, जानकारी लेने का बदलता तरीका और उनके विकास को आकार देने वाले बदलते सामाजिक ढाँचों पर विचार किया जाए। तदनुसार, समाज ऐसे सुधार करें जिनसे इस पीढ़ी में ज़्यादा सब्र रखने, ज़्यादा तार्किक सोच विकसित करने और सम्मानजनक बातचीत को बढ़ावा मिलें।

जेन ज़ी को बनाने वाले सबसे बड़े और असरदार कारणों में से एक है, हाइपर-कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में उनकी परवरिश। कम उम्र से ही, यह पीढ़ी ऐसे माहौल में रही है जहाँ जानकारी, मनोरंजन और बातचीत उनकी उंगलियों पर आसानी से मिल जाती है। स्मार्टफ़ोन, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और हाई-स्पीड इंटरनेट ने तुरंत मिलने वाले फ़ायदे का एक इकोसिस्टम बनाया है। अपडेट के साथ नोटिफ़िकेशन आते हैं, न्यूज़ साइकिल मिनटों में रिफ़्रेश हो जाती हैं, और मनोरंजन ऑन डिमांड उपलब्ध होता है। तुरंत फ़ीडबैक और आसानी से मिलने वाले कंटेंट की यह लगातार स्ट्रीम अनजाने में ही डेवलप हो रहे दिमाग को जल्दी नतीजे और तुरंत इनाम की उम्मीद करने के लिए ट्रेन कर सकती है। इसलिए, जिन हालात में सब्र की ज़रूरत होती है, जैसे जवाब का इंतज़ार करना, कोई लंबा काम पूरा करना, या धीरे-धीरे, सोच-समझकर सीखना, वे फ़्रस्ट्रेटिंग और अनचाही लग सकती हैं। ऑनलाइन बातचीत का तेज़ नेचर, जहाँ छोटे मैसेज और थोड़ी देर का कंटेंट ज़्यादा होता है, लगातार ध्यान और गहरी बातचीत के लिए कम टॉलरेंस में भी योगदान दे सकता है, जिससे बेसब्री का कल्चर बढ़ता है। उदाहरण के लिए, मैसेजिंग ऐप पर तुरंत जवाब की उम्मीद या सोशल मीडिया फ़ीड पर तेज़ी से स्क्रॉल करने से लोग तुरंत संतुष्टि की उम्मीद करने लगते हैं, जिससे असल दुनिया की बातचीत की धीमी रफ़्तार मुश्किल लगने लगती है। नई चीज़ों और तेज़ी से जानकारी के इस लगातार संपर्क से बोरियत की क्षमता भी कम हो सकती है, एक ऐसी स्थिति जो अक्सर सोचने और क्रिएटिव प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स के विकास को बढ़ावा देती है। जब डिजिटल ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बोरियत तुरंत दूर हो जाती है, तो सब्र और सेल्फ-रेगुलेशन विकसित करने के मौके कम हो जाते हैं।

डिजिटल युग ने जानकारी को डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है, जिससे यह पहले से कहीं ज़्यादा आसानी से मिलने वाली हो गई है। लेकिन, इस एक्सेसिबिलिटी के साथ एक बड़ी चुनौती आती हैः उपलब्ध जानकारी की बहुत ज़्यादा मात्रा और अक्सर अनवेरिफाइड नेचर। जेन ज़ी, जो इस बहुतायत के साथ बड़ा हुआ है, अक्सर शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट, सोशल मीडिया फीड्स और वायरल ट्रेंड्स के ज़रिए जानकारी लेता है। इस्तेमाल का यह तरीका क्रिटिकल इवैल्यूएशन और लॉजिकल एनालिसिस के बजाय इमोशनल रेजोनेंस और तुरंत एंगेजमेंट को प्रायोरिटी दे सकता है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने वाले एल्गोरिदम यूज़र्स को एंगेज रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अक्सर ऐसा कंटेंट दिखाकर जो उनके मौजूदा बायस से मेल खाता है या मज़बूत इमोशनल रिस्पॉन्स को उकसाता है। इससे इको चैंबर बन सकते हैं, जहाँ लोग मुख्य रूप से उन नज़रियों के संपर्क में आते हैं जो उनके अपने नज़रियों को कन्फर्म करती हैं, जिससे अलग-अलग नज़रियों से जुड़ने और बारीक समझ डेवलप करने की उनकी क्षमता में रुकावट आती है। नतीजतन, भरोसेमंद सोर्स और गलत जानकारी के बीच अंतर करना एक मुश्किल काम बन जाता है। ₹फेक न्यूज़₹ और सेंसेशनलाइज्ड कंटेंट के फैलने से युवाओं के लिए मज़बूत क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, कम जानकारी के आधार पर जल्दी से राय बनाने का दबाव, जो अक्सर ऑनलाइन बहस और तेज़ी से की जाने वाली कमेंट्री से और बढ़ जाता है, बेतुके तर्कों को अपनाने या बिना सबूत वाले दावों को मानने की ओर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉन्सपिरेसी थ्योरी की लोकप्रियता, जिनमें अक्सर अनुभव के सबूत नहीं होते लेकिन वे भावनात्मक रूप से मज़बूत होती हैं, यह दिखाती है कि बिना वेरिफ़ाई की गई जानकारी कैसे लोगों का ध्यान खींच सकती है और तर्क पर असर डाल सकती है। उन्हें कैसे जांचा जाए, इस बारे में पूरी गाइडेंस के बिना विभिन्न नज़रिया के लगातार संपर्क में रहने से कन्फ्यूजन हो सकता है और सिस्टमैटिक, लॉजिकल तरीकों के बजाय ह्यूरिस्टिक्स या भावनात्मक अपील पर भरोसा हो सकता है।

'मैनर्स' की परिभाषा खुद एक जैसी नहीं है; यह सोशल नॉर्म्स और टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ बदलती रहती है। जेन ज़ी की बातचीत काफी हद तक डिजिटल कम्युनिकेशन पर निर्भर करती है। टेक्स्टिंग, डायरेक्ट मैसेजिंग और ऑनलाइन कमेंट्स में अक्सर बिना बोले इशारे, आवाज़ का टोन और सोशल कॉन्टेक्स्ट की कमी होती है जो आमने-सामने की बातचीत के लिए ज़रूरी हैं। उदाहरण के लिए, एक साफ-साफ टेक्स्ट मैसेज भेजने वाले के लिए एक अच्छी बातचीत हो सकती है, लेकिन पाने वाला इसे खारिज करने वाला या बदतमीज़ी समझ सकता है, खासकर अगर उसमें ग्रीटिंग या आखिर में बात करने जैसी आम तमीज़ न हो। इसके अलावा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलने वाली गुमनामी या दूरी से हिचकिचाहट कम हो सकती है, जिससे ज़्यादा गुस्सैल या बेपरवाह व्यवहार हो सकता है जो शायद सीधे, आमने-सामने की मुलाकातों में न हो। इसके अलावा, पेरेंटिंग स्टाइल में बदलाव, कुछ स्टडीज़ में ज़्यादा छूट देने वाली पेरेंटिंग का ट्रेंड बताया गया है, अनजाने में बच्चों के लिए ज़रूरी सोशल दक्षता, जैसे हमदर्दी, झगड़े सुलझाना, और अथॉरिटी वाले लोगों या अलग राय का सम्मान करने के मौके कम कर सकता है। जब बच्चों को नतीजों से बचाया जाता है या सही सोशल बिहेवियर के लिए लगातार गाइड नहीं किया जाता है, तो उन्हें तमीज़ से बातचीत के लिए ज़रूरी सेल्फ-डिसिप्लिन और दूसरों के लिए सोच-विचार डेवलप करने में मुश्किल हो सकती है।

आज शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे लोग क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जीजाबाई (शिवाजी की माँ) जैसी माँ नहीं हैं। एक बच्चे की अच्छी परवरिश उसे देशभक्त और भविष्य का नागरिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जेन ज़ी में कही जा रही अनुशासनहीनता को ठीक करने के लिए पूरे समाज को एक साथ और कई तरह के तरीके अपनाने की ज़रूरत है। सिर्फ़ बुराई करने से आगे बढ़कर ऐसे रचनात्मक दखल पर ध्यान देना ज़रूरी है जो सकारात्मक विकास को बढ़ावा दें।

इन चुनौतियों से निपटने का एक तरीका डिजिटल साक्षरता और क्रिटिकल सोचने-समझने के कौशल को बढ़ाना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को स्टूडेंट्स को डिजिटल दुनिया में ज़िम्मेदारी से संचालन करना सिखाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें गलत जानकारी की पहचान करने, एल्गोरिदमिक बायस को समझने और ऑनलाइन सोर्स की क्रेडिबिलिटी को एवैल्यूएट करने के बारे में साफ इंस्ट्रक्शन शामिल हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना सिर्फ़ एक एकेडमिक कोशिश नहीं है; इसके लिए अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। डिबेट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिनमें कई सोर्स से जानकारी को सिंथेसाइज़ करने की ज़रूरत होती है, और ऐसी डिस्कशन्स जिनमें कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमाज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, ये सभी ज़्यादा लॉजिकल रीज़निंग डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। माता-पिता और शिक्षक खुलकर इस पर चर्चा करके क्रिटिकल थिंकिंग का मॉडल बना सकते हैं कि वे जानकारी को कैसे एवैल्यूएट करते हैं और राय कैसे बनाते हैं।

पेशेंस को बढ़ावा देने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए सोच-समझकर कोशिश करने की ज़रूरत होती है जो इसे बढ़ावा दे। यह घर और स्कूल दोनों जगह से शुरू हो सकता है। स्क्रीन टाइम कम करना और ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना जिनमें लगातार फोकस की ज़रूरत होती है, जैसे किताबें पढ़ना, हॉबीज़ में शामिल होना, बोर्ड गेम खेलना, या स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, देर से मिलने वाली खुशी को सहने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। स्कूल ऐसे असाइनमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जिनमें लंबे समय तक कमिटमेंट और लगन की ज़रूरत हो, जिससे स्टूडेंट्स को मेहनत की कीमत और लगातार काम करके लक्ष्य हासिल करने की संतुष्टि सिखाई जा सके। सिर्फ़ नतीजों को ही नहीं, बल्कि कोशिश और प्रोसेस को भी सेलिब्रेट करने से फोकस तुरंत नतीजों से हटकर सीखने और डेवलपमेंट की यात्रा पर जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी मुश्किल काम के लिए स्टूडेंट्स के डेडिकेशन को पहचानना और इनाम देना, चाहे तुरंत सफलता मिले या न मिले, लगन की अहमियत को और मज़बूत कर सकता है।

मैनर्स और आपसी व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए सोशल-इमोशनल लर्निंग पर फोकस करना ज़रूरी है। स्कूलों और परिवारों को एक्टिवली एम्पैथी, सम्मान और असरदार कम्युनिकेशन सिखाना और उसका उदाहरण देना चाहिए। सोशल-इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम को एजुकेशनल फ्रेमवर्क में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को अपनी भावनाओं को समझने और मैनेज करने, अच्छे रिश्ते बनाने और ज़िम्मेदार फ़ैसले लेने के लिए टूल्स मिलें। कम्युनिटी सर्विस या वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देने से युवाओं को अलग-अलग तरह के अनुभव मिल सकते हैं और उनमें ज़्यादा समझदारी बढ़ सकती है।

शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाने में स्पष्टता नहीं: हाई कोर्ट

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में बिना स्थान चिह्नित किए शराब दुकान का लाइसेंस देने के मामले को गंभीरता से लिया है और आबकारी आयुक्त को शराब नीति के साथ 12 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विनय सरन की खंडपीठ ने आगरा के विजय कुमार कुलश्रेष्ठ की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बार-बार शराब की दुकानों के लाइसेंस बिना यह स्पष्ट किए जारी किए जाते रहे हैं कि दुकान किस विशिष्ट स्थान पर स्थापित की जानी है।

याची की तरफ से अधिवक्ता श्रीकृष्ण शुक्ल ने बहस की। खंडपीठ ने शराब की दुकानों के लाइसेंस देने की मौजूदा नीति पर सवाल उठाया है। याची ने कोर्ट में शिकायत की थी कि उनके घर के ठीक सामने शराब की दुकान खोल दी गई है, इससे उन्हें परेशानी हो रही है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समय-समय पर कई आदेश पारित किए। कोर्ट के बीते 21 मई के आदेश के अनुपालन में आगरा के जिला आबकारी अधिकारी कृष्ण पाल यादव व्यक्तिगत हलफनामे के साथ पेश हुए थे।

उस दिन अधिकारियों ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि याची के घर के सामने शराब दुकान को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्तिकेय सरन के अनुरोध पर मामले को छह जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी इस निर्देश दिया था कि उस दिन भी वही अधिकारी उपस्थित रहें। राज्य सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता राजेश कुमार पाल ने भी पैरवी की।

देवरिया में 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

आर्यावर्त संवाददाता

भाटपाररानी/लार, (देवरिया)। गोवध के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गुरुवार देर रात लार और भाटपाररानी पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है। उसके पास से तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भाटपाररानी पुलिस चनुकी मोड़ पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बाइक से पहुंचे संदिग्ध युवक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। वह पुलिस को चकमा देकर बाइक से भाग निकला। इसकी सूचना लार पुलिस को दी गई। इसके बाद लार पुलिस ने खरवनिया मोड़ के पास घेराबंदी कर दी।

पुलिस टीम को सामने देखकर आरोपित ने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन अनियंत्रित होकर बाइक समेत सड़क पर गिर गया। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद उसने तमंचे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा।

पूछताछ में आरोपित की पहचान अजहर अंसारी पुत्र अहमद अंसारी, निवासी मटियरा जगदीश, थाना लार के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, वह भाटपाररानी थाने में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में वांछित था। गिरफ्तारी नहीं होने पर उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस ने लार थाने में आरोपित के खिलाफ पुलिस टीम पर फायरिंग के मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

संक्षेप

नाली विवाद चले में लाठी-डंडे

जौनपुर । खुटहन थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में नाली निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पूरी वारदात को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

पेंशनर्स की बैठक 10 अगस्त को

जौनपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के जनपद अध्यक्ष सी बी सिंह एवं जिला मन्त्री कृपाशंकर उपाध्याय ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती से अवगत कराया है कि मासिक बैठक द्वितीय शनिवार को अवकाश होने के कारण अगले कार्य दिवस 10 अगस्त पुर्वान्ह साढे ग्यारह वजे से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स कार्यालय पर होगी ।

चोरी में में फरार युवक-युवती गिरफ्तार

जौनपुर। बरसठी थाने पुलिस ने चोरी के एक मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त और एक अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक-एक सफेद धातु की पायल बरामद की है।पुलिस के अनुसार इस दौरान थाना बरसठी पर दर्ज , धारा 305, 352, 351(3) एवं 317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त आनन्द गौतम पुत्र राहुल कुमार गौतम तथा अभियुक्ता प्रतिभा गौतम उर्फ अजोरा पुत्री अखिलेश कुमार गौतम, निवासी ग्राम जयरामपुर, थाना बरसठी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक-एक सफेद धातु की पायल बरामद की है।

20 करोड़ से होगा 19 नई सड़कों के निर्माण

जौनपुर । बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-2026 के तहत लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से 19 नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।लोक निर्माण विभाग ने इन सभी प्रस्तावित मार्गों का प्राक्कलन (अनुमानित लागत) तैयार कर शासन को भेज दिया है। अब वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि क्षेत्र के विभिन्न गांवों में वर्षों से लंबित संपर्क मार्गों के निर्माण की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी। इसके बाद विभाग ने सर्वेक्षण कर यह प्रस्ताव तैयार किया। इन नई सड़कों के निर्माण से बदलापुर और महाराजगंज विकासखंड के दर्जनों गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी।

ई-रिक्शा चालकों में मारपीट से मार्ग बाधित

जौनपुर । नगर कोतवाली चैराहे पर शुक्रवार पूर्वान्ह तीन ई-रिक्शा चालकों के बीच सवारी बैठाने को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद जल्द ही हाथापाई में बदल गया, जिससे चैराहे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात बाधित हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हनुमान मंदिर के पास सवारी बैठाने को लेकर चालकों में कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते यह मारपीट में बदल गई, जिसके कारण चैराहे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही चैराहे पर तैनात पिकेट और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए तीनों चालकों को अलग किया और स्थिति को शांत कराया। इसके बाद यातायात को सुचारु रूप से बहाल किया जा सका। पुलिस की सक्रियता से किसी बड़ी अप्रिय घटना को टाल दिया गया। लोगों का कहना है कि कोतवाली चैराहा शहर के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक है। यहां ई-रिक्शा के अव्यवस्थित संचालन और मनमाने तरीके से सवारी भरने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।

नहर में मिला अधेड़ का षव, हत्या का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के थलोई गांव में भूमि विवाद के दौरान साजिश रचकर हत्या करने का आरोप मृतक के पुत्र ने लगाया है। मामले में एक अगस्त को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जबकि गुरुवार को महराजगंज थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव में शव मिला जिसकी शिनाख्त थलोई निवासी 49 वर्षीय अशोक कुमार पटेल के रूप में हुई है। शिनाख्त के बाद घटना की सूचना जब ग्रामीणों को हुई तो भारी भीड़ कोतवाली पहुंच गई तो भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने के आश्वासन पर लोग वापस लौट गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के पुत्र आकाश कुमार पटेल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनका अपने परिवार और पड़ोसियों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। विपक्षी की भटपुरा में रिश्तेदारी है और वे सब रिश्तेदारों के साथ साजिश रचकर पिता अशोक कुमार पटेल की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिए। आकाश का कहना है कि एक अगस्त को उनके पिता घर से 8 बजे स्प्लेंडर बाइक से निकले थे और फिर लौट कर घर वापस नहीं लौटे। मामले में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पांच दिन बाद भटपुरा गांव की नहर से क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है, जिसका हाथ,पैर कटा था।मामले में आरोपी ईश्वर लाल उनकी पत्नी फूलकली,उनके पुत्र अंकित, अमरेंद्र पटेल, कविता समेत अन्य लोगों को नामजद करते हुए साजिश रचकर पिता की हत्या कराने का आरोप लगाया है। उक्त मामले के बावत प्रभारी निरीक्षक विनीत राय का कहना है कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ग्रामीणों की भीड़ को समझा बुझा कर आक्रोश शांत करा दिया गया है।

आजमगढ़ में एम्बुलेंस नहीं मिलने से मासूम ने पिता की गोद में तोड़ा दम, दावों की खुली कलई

आर्यावर्त संवाददाता

आजमगढ़। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही ने एक 11 वर्षीय मासूम की जिंदगी छीन ली। मऊ जिले के रानीपुर फतेहपुर निवासी अंश की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे समय पर 108 एंबुलेंस नहीं मिलने का आरोप है। स्वजन का कहना है कि इलाज के लिए वाराणसी ले जाने में हुई देरी के कारण रास्ते में ही पिता की गोद में उसकी मौत हो गई।

इस घटना ने एक बार फिर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और रेफरल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम अंश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्वजन उसे पहले चिरैयाकोट के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए राजकीय मेडिकल कालेज, चक्रपानपुर रेफर कर दिया। मेडिकल कालेज में जांच के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि बच्चे को तत्काल वेंटिलेटर की आवश्यकता है, लेकिन वहां कोई वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। इसके बाद उसे बीएचयू, वाराणसी रेफर कर दिया गया। पीड़ित पिता अमित का आरोप है कि उन्होंने 108 एंबुलेंस सेवा पर कई बार फोन किया, लेकिन हर बार उन्हें केवल ₹10 मिनट में एंबुलेंस पहुंचनेर का आश्वासन मिलता रहा।

कहना है कि करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार करने के बावजूद एंबुलेंस नहीं पहुंची, जबकि इस दौरान बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती रही। सरकारी एंबुलेंस न मिलने पर स्वजन ने उधार और मदद से निजी एंबुलेंस की व्यवस्था की और बच्चे को वाराणसी के लिए रवाना किया। बीएचयू पहुंचने से पहले ही रास्ते में अंश ने पिता की गोद में अंतिम सांस ले ली। मेडिकल कालेज के चिकित्सक डॉ. कृष्णकांत ने बताया कि बच्चे के फेफड़ों में पानी भर गया था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी। कहा कि बीएचयू से भी संपर्क किया गया था। वहीं, पिता अमित का कहना है कि यदि समय पर एंबुलेंस मिल जाती तो शायद उनके बेटे की जान बचाई जा सकती थी।घटना के बाद स्वजन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

लूट के माल का बंटवारा कर रहे थे बदमाश . . . पुलिस से मुठभेड़ के बाद पांच गिरफ्तार, 12 किलो आभूषण बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। रायबरेली के मिल एरिया पुलिस और एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ के बाद हुई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 12.80 किलोग्राम चोरी के आभूषण और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक रायबरेली रवि कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली। 6/7 अगस्त 2026 की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति लोनियन का पुरवा, शारदा नहर पुल के पास चोरी के माल का बंटवारा कर रहे थे। वे किसी अन्य स्थान पर चोरी की योजना भी बना रहे थे। मिलएरिया पुलिस ने उन्हें घेरने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में शिवकुमार और बबलू के पैर में गोली लगी। तीन अन्य बदमाश राकेश उर्फ छोटे, लवकुश और सागर वर्मा मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया।

बरामदगी और अभियुक्तों का विवरण

घायल शिवकुमार और बबलू को उपचार के लिए सीएचसी अमांवा भेजा गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस और एक स्विफ्ट डिजायर कार (UP32NV1225) बरामद की है। बरामद आभूषणों में 4.460 किलोग्राम मोहनगंज, अमेठी की चोरी से संबंधित हैं। शेष आभूषण मिलएरिया क्षेत्र के तकिया चौराहा स्थित ज्वेलर्स की दुकानों से चोरी हुए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में सागर वर्मा एक सुनार है।

गांव के प्रवेश द्वार पर ग्राम सूचना बोर्ड लगायें

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय पर वी०बी०-जी० राम प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सर्वप्रथम अपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं के कार्य लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा प्रत्येक कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। एम०डी०एम शेडों, तालाबों एवं अमृत सरोवरों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्नपूर्णा भवनों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप शीघ्र पूर्ण कराया जाए ताकि जनसामान्य को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने सक्रिय जॉब कार्ड धारकों के ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र श्रमिकों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन मास्टर रोल जारी करने की स्थिति की समीक्षा की तथा कार्यों की आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से मास्टर रोल जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत के मुख्य प्रवेश द्वार पर ग्राम सूचना बोर्ड स्थापित कराने के निर्देश दिए। इस बोर्ड पर गांव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कुल जनसंख्या, महिला एवं पुरुष जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या, ग्राम प्रधान का नाम, भू-जल (ग्राउंड वाटर) की स्थिति, ग्राम की प्रमुख उपलब्धियां तथा विलेज सिटीजन चार्टर अंकित किया जाए।

12 साल की दहशत का खात्मा, हत्या और नशे के कारोबार से लेकर 'सीजेपी' के आंदोलन तक

आर्यावर्त संवाददाता

शामली। शामली जिले के झिंझाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान के तार तीन राज्यों से जुड़े हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि फुरकान लूट और रंगदारी की वारदातों की आड़ में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार भी चला रहा था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल में नशा तस्करी से जुड़े कई लोगों के साथ उसके संपर्क होने का खुलासा हुआ है।

पुलिस की जांच के अनुसार, फुरकान पंजाब के अमृतसर और फिरोजपुर, असम के म्यांमार बॉर्डर क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश के बरेली से नशे की खेप मंगवाता था। इस खेप को वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करता था। इस अवैध धंधे में उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल कर रखा था। पुलिस को फुरकान के तीन सोशल मीडिया अकाउंट मिले हैं, जिनकी जांच से पता चला है कि वह कैराना के अलावा हरियाणा के पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम के कई लोगों के संपर्क में था। पुलिस अब इन सभी संपर्कों की गहन जांच कर रही है और इस नशीले नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।

पत्नी भी नशा तस्करी में गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि फुरकान ने अपनी पत्नी रेशमा और अन्य रिश्तेदारों की मदद से नशे का कारोबार शुरू किया था। लगभग एक वर्ष पूर्व उसकी पत्नी रेशमा को भी नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो करीब पांच महीने पहले ही जमानत पर रिहा हुई है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि फुरकान नशे के कारोबार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल अपने आपराधिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करता था। इसी धंधे की आड़ में वह रंगदारी और लूट जैसी वारदातों को भी अंजाम देता रहा।

पहचान छिपाने के लिए अपनाता था ये तरीके

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, फुरकान पुलिस को भ्रमित करने के लिए दाढ़ी रखता था और कंधे पर तौलिया डालकर चलता था। पंजाब और हरियाणा में रहने के दौरान उसने कई लोगों के सामने खुद को 'हाफिज' के तौर पर पेश किया और कहा कि वह मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, ताकि उस पर कोई शक न करे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि फुरकान पुलिस से बचने के लिए अपने परिवार के साथ पंजाब में बसने की योजना बना रहा था और इसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी थीं।

बैग से मिले कारतूस, वारदात की थी तैयारी?

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद फुरकान के पास से एक बैग बरामद किया था। इस बैग में उसके कपड़े और 30 से अधिक कारतूस मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि फुरकान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। बरामद सामान की विस्तृत जांच की जा रही है।

राजनीतिक आंदोलन में भी रहा शामिल

पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि फुरकान हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक आंदोलन में भी शामिल हुआ था। पुलिस को इस संबंध में अहम जानकारी मिली है और वह फुरकान के दिल्ली प्रवास और उसके संपर्कों की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, मन्ना माजरा गांव का एक युवक फुरकान के लगातार संपर्क में था और दोनों दिल्ली में आंदोलन के दौरान करीब दो दिन साथ रहे। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फुरकान आंदोलन में किन-किन लोगों से मिला और वहां जाने का उसका असली मकसद क्या था। पुलिस आंदोलन स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटा रही है और फुरकान के मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट व अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसके संपर्कों की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं फुरकान ने आंदोलन की आड़ में अपने नेटवर्क का विस्तार करने या राजनीतिक शरण लेने की योजना तो नहीं बनाई थी।

मुकीम काला गैंग के सदस्यों पर भी पुलिस की नजर

कुख्यात मुकीम काला और फुरकान के मारे जाने के बाद पुलिस की नजर दोनों गिरोहों के बचे हुए सदस्यों पर टिकी हुई है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, मुकीम काला गैंग के अधिकांश सदस्य या तो जेल में हैं या पुलिस कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। पुलिस गिरफ्त से बाहर बचे सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है। वर्ष 2021 में चित्रकूट जेल में गैंगवार में मुकीम काला की मौत के बाद उसके करीबी रिजवान ने गिरोह की कमान संभाली थी। पुलिस की लगातार कार्रवाई से गिरोह का नेटवर्क कमजोर पड़ा है और अधिकांश सदस्य कानून के शिकंजे में आ गए हैं।

मुकीम काला गैंग के प्रमुख सदस्य

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मुकीम काला गैंग के कुल 14 प्रमुख सदस्य थे। इनमें से दो (मुकीम काला और अरशद) मारे जा चुके हैं, आठ सदस्य विभिन्न जेलों में बंद हैं, तीन सदस्य जेल से बाहर हैं, जबकि एक सदस्य पुलिस रडार से बाहर है।

मौतः मुकीम काला, अरशद (बढ़ी माजरा)

जेल में बंदः शेख जादानगर (तितरो), हैदर (तितरो), महताब (बलवा), नीरज (लांक), मुनसाद (खंद्रावली), बशर (हाजीपुरा) सहित अन्य सदस्य।

जेल से बाहरः रिजवान (जहानपुरा), हारून (बरनावी), आसिफ (खंद्रावली)।

पुलिस रडार से बाहरः फरमान (भूरा गांव)।

राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी

कैराना पलायन प्रकरण के मुख्य आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कानून-व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। पार्टी कैराना पलायन और फुरकान एनकाउंटर को जोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने का प्रयास कर सकती है। वहीं, विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गया है।

प्रेग्नेंसी में किन विटामिन्स और मिनरल्स की होती है ज्यादा जरूरत?

प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर को कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। ये मां और गर्भ में पल रहे बच्चे के बेहतर विकास में मदद करते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई बदलाव होते हैं। इस समय मां और गर्भ में पल रहे बच्चे, दोनों को सही पोषण की जरूरत होती है। इसलिए इस दौरान सिर्फ ज्यादा खाना नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर खाना खाना ज्यादा जरूरी माना जाता है। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत भी सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है। ऐसे में इनके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि मां और बच्चे दोनों को जरूरी पोषण मिल सके।

सही मात्रा में जरूरी पोषक तत्व मिलने से मां और गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सकती है। वहीं, किसी जरूरी विटामिन या मिनरल की कमी होने पर खून की कमी, हड्डियां कमजोर होना, बच्चे के विकास पर असर पड़ना और प्रेग्नेंसी से जुड़ी कुछ परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस दौरान खानपान पर खास ध्यान देना जरूरी होता है। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी में किन विटामिन्स और मिनरल्स की ज्यादा जरूरत होती है और इनके लिए क्या खाना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में किन विटामिन्स और मिनरल्स की ज्यादा जरूरत होती है?

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज (NIDDK) के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, आयोडीन और विटामिन बी12 की जरूरत सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है। ये पोषक तत्व गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ, दिमाग, हड्डियों और दूसरे अंगों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही, ये मां के शरीर को भी स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आयरन खून बनने में मदद करता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, जबकि फोलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सही विकास में मदद करता है।

विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अच्छी तरह इस्तेमाल करने में मदद करता है। आयोडीन बच्चे के दिमाग और नर्वस सिस्टम के विकास के लिए जरूरी है, जबकि विटामिन बी12 रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इन सभी पोषक तत्वों की सही मात्रा मां और बच्चे, दोनों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी मानी जाती है।

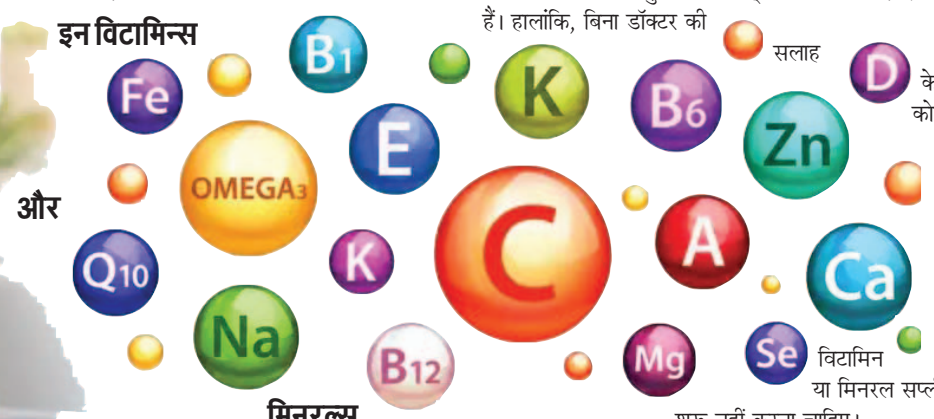

क्या प्रेग्नेंसी में सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है?

प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत सिर्फ खाने से पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में डॉक्टर जरूरत के अनुसार सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकते हैं। हालांकि, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट शुरू नहीं करना चाहिए।

जरूरत से ज्यादा मात्रा में सप्लीमेंट लेना भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही सप्लीमेंट्स लें और साथ में संतुलित खानपान पर भी ध्यान दें।

मिनरल्स के लिए क्या खाएं?

इन जरूरी पोषक तत्वों के लिए अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स, दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, साबुत अनाज, फल, मेवे और बीज शामिल करें। अलग-अलग तरह के फूड्स खाने से शरीर को कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकते हैं।

अगर आप शाकाहारी हैं, तो दालें, सोया, दूध और दूध से बनी चीजें भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ताजा और संतुलित खाना खाने की कोशिश करें, ताकि मां और बच्चे दोनों को जरूरी पोषण मिल सके।

प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए? जानिए किन चीजों से बनानी चाहिए दूरी

गर्भावस्था (प्रेगनेंसी) हर महिला के जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण चरण होता है। इस दौरान मां जो भी खाती-पीती है, उसका सीधा असर शिशु के विकास पर पड़ता है। इसलिए पौष्टिक आहार जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कुछ ऐसी चीजों से बचना जो मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।

कच्चा या अधपका मांस और अंडा

कच्चे या अधपके मांस, चिकन, मछली और अंडे में साल्मोनेला और लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग और गर्भस्थ शिशु के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। हमेशा अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही खाएं।

बिना पाश्चुरीकृत दूध और डेयरी उत्पाद

कच्चा दूध और उससे बने कुछ चीज़ में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। हमेशा पाश्चुरीकृत दूध और डेयरी उत्पादों का ही सेवन करें।

अधिक पारे वाली मछलियां

कुछ बड़ी मछलियों में पारे की मात्रा अधिक होती है, जो शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास को प्रभावित कर सकती है। सुरक्षित विकल्पों के बारे में डॉक्टर से सलाह लें।

शराब और धूम्रपान

गर्भावस्था के दौरान शराब और तंबाकू का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये समय से पहले प्रसव, कम वजन वाले बच्चे और जन्मजात समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

ज्यादा कैफीन

चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन होता है। अधिक मात्रा में कैफीन लेने से गर्भावस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें।

जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड

पिज्जा, बर्गर, चिप्स, पैकेट वाले स्नैक्स और अत्यधिक तले-भुने खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा अधिक होती है। इनका ज्यादा सेवन वजन बढ़ने और गर्भकालीन मधुमेह जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है।

अधुले फल और सब्जियां

फल और सब्जियां खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना जरूरी है। इनमें मौजूद कीटनाशक या बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बन सकते हैं।

सड़क किनारे खुले में मिलने वाला भोजन

खुले में रखा हुआ या अस्वच्छ वातावरण में तैयार भोजन संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। गर्भावस्था में ताजा और स्वच्छ भोजन को प्राथमिकता दें।

बिना डॉक्टर की सलाह के हर्बल सप्लीमेंट

सभी हर्बल उत्पाद गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं होते। किसी भी सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक दवा या जड़ी-बूटी का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना न करें।

स्वस्थ गर्भावस्था के लिए क्या खाएं?
ताजे फल और हरी सब्जियां
साबुत अनाज
दालें और प्रोटीन युक्त भोजन
दूध, दही और पनीर (पाश्चुरीकृत)
पर्याप्त पानी
डॉक्टर द्वारा बताए गए आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड सप्लीमेंट
ध्यान रखें

हर महिला की गर्भावस्था अलग होती है। यदि आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायरॉयड या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो अपने आहार में बदलाव करने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें।

मोबाइल स्क्रीन के संपर्क में आ सकती है त्वचा, इन 5 तरीकों से पड़ता है असर

आजकल मोबाइल हर किसी की जरूरत बन गया है। हम इसका इस्तेमाल रोजाना घंटों तक करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल स्क्रीन का आपके चेहरे पर क्या असर पड़ता है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताते हैं, जिनके कारण मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके बाद आप अपनी त्वचा की देखभाल के लिए सही कदम उठा सकें।

मोबाइल स्क्रीन की गर्मी

जब आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा उसके करीब होता है। मोबाइल स्क्रीन गर्म हो जाती है, खासकर जब आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं।

यह गर्माहट आपके चेहरे की त्वचा को प्रभावित कर सकती है, जिससे जलन, लालिमा या दाने हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करें तो उसे थोड़ी दूरी पर रखें या हेडसेट का उपयोग करें।

कीबोर्ड के निशान

मोबाइल कीबोर्ड पर टाइप करते समय उंगलियों के निशान रह जाते हैं।

जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो ये निशान भी आपके चेहरे पर आ सकते हैं। इससे मुंहासे और त्वचा पर खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने फोन को साफ रखें और नियमित रूप से उसकी सफाई करें।

इसके अलावा कीबोर्ड को भी साफ करते रहें ताकि बैक्टीरिया न बढ़ें और आपकी त्वचा स्वस्थ रहे।

नीली रोशनी का असर

मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी भी आपकी त्वचा पर असर डाल सकती है। यह रोशनी आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है और समय के साथ उम्र बढ़ने के लक्षणों को बढ़ा सकती है।

इससे बचाव के लिए आप अपने फोन पर नीली रोशनी फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या रात को सोने से पहले इसे बंद कर सकते हैं।

इसके अलावा आप नीली रोशनी से बचाने वाले त्वचा देखभाल उत्पादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

बैक्टीरिया का खतरा

हमारा फोन रोजाना कई जगहों पर जाता है और हर जगह बैक्टीरिया होते हैं।

जब आप अपने फोन को अपने चेहरे से लगाते हैं तो ये बैक्टीरिया आपकी त्वचा पर आ जाते हैं, जिससे संक्रमण या दाने हो सकते हैं।

इससे बचाव के लिए अपने फोन को नियमित रूप से साफ करें और कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का फोन इस्तेमाल न करें।

इसके अलावा अपने फोन को अपने बैग या जेब में रखने से बचें।

स्क्रीन सुरक्षा कवर

अगर आप अपने फोन को बिना किसी कवर के रखते हैं तो यह भी एक बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि फोन कवर भी बैक्टीरिया से भरा होता है। इसलिए इसे बार-बार साफ करना जरूरी है।

इसके अलावा एक अच्छा स्क्रीन सुरक्षा कवर भी इस्तेमाल करें जो बैक्टीरिया को रोक सके।

इन सभी तरीकों का पालन करके आप अपने चेहरे को मोबाइल स्क्रीन से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं।

लंच बॉक्स को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

लंच बॉक्स में खाने की तैयारी करना एक कला है, जो आपके दिनभर की ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। सही पोषण आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने लंच बॉक्स को अधिक पौष्टिक और संतुलित बना सकते हैं, जिससे आपका दिन बेहतर हो सके।

सब्जियों का उपयोग बढ़ाएं

सब्जियां आपके लंच बॉक्स का अहम हिस्सा होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, और बथुआ विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। इनमें फाइबर भी होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है।

इन्हें अपने लंच बॉक्स में शामिल करने से आपकी ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है और आपको थकान महसूस नहीं होती।

सब्जियों को हल्का सा भूनकर या भाप में पकाकर खाने से उनका स्वाद बढ़ जाता है और पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं।

प्रोटीन का ध्यान रखें

प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि यह मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर को ऊर्जा देती है।

इसके लिए आप अपने लंच बॉक्स में दाल, चना, राजमा या छोले जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं। इनका सेवन करने से आपको भरपूर प्रोटीन मिलती है और यह आपके शरीर को ताकत देती है।

प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन दिनभर की थकान को दूर करता है और आपको तरोताजा महसूस करवाता है।

फलों को शामिल करें

फल विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

साथ ही ये आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं। अपने लंच बॉक्स में एक या दो फल जैसे सेब, केला या संतरा जरूर रखें।

इनका सेवन करने से आपको ताजगी महसूस होगी और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। फलों का सेवन न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से भी तरोताजा रखता है।

पानी पीते रहें

पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।

अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो एक छोटी बोतल में पानी भरकर ले जाएं और समय-समय पर उसे पूरा करें। इससे आपका पाचन ठीक रहेगा और शरीर में हानिकारक तत्व भी बाहर निकलेंगे।

पानी पीने से आपको थकान महसूस नहीं होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

स्नैक्स पर ध्यान दें

स्नैक्स भी लंच बॉक्स का अहम हिस्सा होते हैं। चिप्स या बिस्किट खाने की बजाय नट्स, मखाना या भुने चने जैसे सेहतमंद विकल्प चुनें।

ये स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषण भी देते हैं। इनसे आपको ऊर्जा मिलती रहती है और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं।

इन सरल सुझावों को अपनाकर आप अपने लंच बॉक्स को पौष्टिक बना सकते हैं, जिससे आपका दिन बेहतर गुजर सकेगा।

ये हैं भारत की 10 सबसे अच्छी कंपनियां जहां हर कोई करना चाहता है काम, लिस्ट में देखें पहले नंबर पर कौन

नौकरी करने वाले हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे एक ऐसी कंपनी मिले जहां काम का ज्यादा तनाव न हो और पैसे भी अच्छे मिलें। अगर आप भी कभी सोचते हैं कि देश में काम करने के लिहाज से सबसे अच्छी कंपनियां कौन सी हैं, तो रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 की नई रिपोर्ट में इसका जवाब छिपा है। इस बड़े सर्वे के मुताबिक, नौकरी के लिए भारत में लोगों की सबसे पहली पसंद गूगल है।

इसके बाद टाटा ग्रुप और अमेजन का नंबर आता है। यह सर्वे दुनिया भर के 34 बाजारों में करीब पौने दो लाख लोगों से बातचीत पर आधारित है। भारत में भी 3500 कर्मचारियों ने अपनी बेबाक राय रखी है। इस रिपोर्ट से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब घर से पूरी तरह काम करने (रिमोट वर्क) का दौर खत्म हो रहा है और ऑफिस व घर दोनों जगह से काम करने का 'हाइब्रिड मॉडल' ही अब नया नियम बन गया है।

पुरानी नौकरी से क्यों ऊब रहे हैं लोग?

पहले लोग सिर्फ तब नौकरी बदलते थे जब उन्हें कहीं और ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सर्वे के नतीजे काफी दिलचस्प हैं। आज के समय में 49 प्रतिशत लोग अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी निजी जिंदगी और दफ्तर के काम के बीच का तालमेल (वर्क-लाइफ बैलेंस) बिगड़ जाता है। इसके अलावा 42 फीसदी लोग करियर में आगे बढ़ने का मौका न मिलने पर और 41 फीसदी लोग कम सैलरी की वजह से इस्तीफा दे देते हैं। अगर उम्र के हिसाब से देखें, तो करियर में ग्रोथ न दिखने पर 43 प्रतिशत मिलेनियल्स, 42 फीसदी जेन-जेड (Gen Z) और 39 प्रतिशत जेन-एक्स (Gen X) कर्मचारी अपनी मौजूदा कंपनी को अलविदा कहना सही समझते हैं।

अब सिर्फ अच्छी सैलरी से नहीं मानेंगे कर्मचारी

साल 2020 के बाद से नौकरीपेशा लोगों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। रैंडस्टैड इंडिया के एमडी नारायण अय्यर बताते हैं कि अब कर्मचारी किसी भी कंपनी को सिर्फ किसी एक फायदे या भत्ते के तराजू पर नहीं तौलते। वे एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां उन्हें हर तरह से संतुष्टि मिले। आज के समय में लगभग आधे कर्मचारी ऐसे हैं जो अगले छह महीनों में अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियों को अब सिर्फ ऊपरी फायदों से आगे बढ़कर सोचना होगा।

नौकरी की सुरक्षा का मतलब भी अब बदल गया है। अब समय पर अच्छी सैलरी (47%) के साथ-साथ काम की तारीफ और करियर का सुरक्षित भविष्य (47%) भी उतना ही जरूरी है। इसके साथ ही, 46 फीसदी कर्मचारी चाहते हैं कि कंपनी के अंदर बातचीत में पूरी पारदर्शिता हो, ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।

नए जमाने के डिजिटल कर्मचारियों की डिमांड

नए जमाने के तकनीकी और डिजिटल कर्मचारियों की सोच बाकी लोगों से काफी अलग है। जहां एक तरफ आम कर्मचारी वर्क-लाइफ बैलेंस को सबसे ऊपर रख रहा है, वहीं डिजिटल क्षेत्र के 73 फीसदी कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है उनकी मोटी सैलरी। इस सेक्टर के 55 फीसदी लोग करियर में ग्रोथ न मिलने पर नौकरी छोड़ने का मन बना लेते हैं। दूसरे सेक्टरों में यह संख्या काफी कम है, जैसे ऑपरेशनल काम करने वालों में यह 40 प्रतिशत और बाकी प्रोफेशनल्स में 43 प्रतिशत है।

भारत की 10 सबसे बेहतरीन कंपनियों की लिस्ट

रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 ने भारत की टॉप 10 कंपनियों की जो सूची जारी की है, वो इस प्रकार है।

गूगल (Google)
टाटा ग्रुप (Tata Group)
अमेजन (Amazon)
सैमसंग इंडिया (Samsung India)
इंफोसिस (Infosys)
रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries)
आईटीसी ग्रुप (ITC Group)
हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever)
महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra)
डेल टेक्नोलॉजीज (Dell Technologies)

2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज? जानें आम यूजर्स पर कितना पड़ेगा असर

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद में 'भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2027' पेश किया है। इस बिल में मर्चेंट डिस्काउंट रेट को फिर से लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत 2000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर चार्ज लगाने की बात कही गई है। इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे और भ्रम फैलने लगे कि अब आम लोगों को यूपीआई से पेमेंट करने पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह 2000 रुपये की लिमिट क्या है और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा।

आम यूजर्स पर नहीं पड़ेगा कोई असर

सबसे पहले यह साफ कर लें कि इस नए प्रस्ताव का आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप दूध, सब्जी, राशन, किराने का सामान खरीदते हैं या फिर ऑटो-टैक्सी का किराया चुकाते हैं, तो आपको पहले की तरह कोई चार्ज नहीं देना होगा। सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव विशेष रूप से 2000 रुपये से अधिक के 'मर्चेंट ट्रांजेक्शन' (व्यापारिक लेन-देन) और बड़े कमर्शियल संस्थानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

कंज्यूमर टू कंज्यूमर पेमेंट रहेगा एकदम फ्री

अगर आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को 2000 रुपये या उससे ज्यादा की रकम भेजते हैं तो यह पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। आम यूजर्स के लिए यूपीआई की सामान्य लिमिट पहले की तरह ही एक लाख रुपये प्रतिदिन बनी रहेगी। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल-कॉलेज की फीस या टैक्स चुकाने जैसी विशेष श्रेणियों में यह लिमिट और भी ज्यादा है।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क (चार्ज) होता है, जो कोई व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के एवज में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को चुकाता है। आसान भाषा में समझें तो यह चार्ज उपभोक्ताओं को नहीं, बल्कि उस व्यापारी (मर्चेंट) को देना होगा जो पेमेंट ले रहा है। यह नियम मुख्य रूप से बैंक, यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स और बड़े व्यापारियों के इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा।

सिर्फ 5त्न लेन-देन ही आएंगे इसके दायरे में

आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीआई के जरिए होने वाले 95 फीसदी ट्रांजेक्शन 2000 रुपये से कम के ही होते हैं। यानी यह नया एमडीआर चार्ज सिर्फ उन 5 फीसदी ट्रांजेक्शन पर ही लागू होगा जो 2000 रुपये से अधिक के होंगे और मर्चेंट अकाउंट में जाएंगे।

कितना लगेगा चार्ज और कब से होगा लागू?

2000 रुपये से ज्यादा के व्यावसायिक लेन-देन पर यह प्रस्तावित शुल्क 0.25त्न से लेकर 0.4त्न के बीच हो सकता है। फिलहाल 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक का चार्ज लगाने पर भी गंभीरता से चर्चा चल रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस नियम को लागू करने की कोई तय समयसीमा (डेडलाइन) निर्धारित नहीं की है। गौरतलब है कि सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2020 में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले लेन-देन पर एमडीआर चार्ज लगाने पर रोक लगा दी थी।

'गद्दारों' की वजह से बैकफुट पर अमेरिका, हथियारों की कमी वाली रिपोर्ट बनी ईरान समझौते में बड़ा रोड़ा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जारी सैन्य तनाव के बीच हथियारों के घटते भंडार को लेकर लीक होती खबरों पर नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने इस हफ्ते हुई कैबिनेट मीटिंग मेंहथियारों के भंडार से जुड़ी गोपनीय जानकारी मीडिया तक पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। उन्होंने ऐसे लोगों को देशद्रोही बताया है।

ट्रंप की चिंता सिर्फ हथियारों की कमी को लेकर नहीं है। उनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक होने से अमेरिका की सैन्य ताकत कमजोर दिखाई दे रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप को कई महीनों से हथियारों के भंडार से जुड़ी संभावित समस्याओं की जानकारी थी। लेकिन ईरान के साथ तनाव के निर्णायक दौर में यह दुनिया के सामने आने से बेहद नाराज हैं।

ट्रंप ने ट्रूथ पर किए अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर भी अमेरिकी हथियारों के भंडार को लेकर सामने आ रही रिपोर्टों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास खास तौर पर कुछ तरह के हथियारों की बड़ी मात्रा मौजूद है। साथ ही नए हथियारों का उत्पादन भी तेजी से किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने बाद में यह भी स्वीकार किया कि कुछ हथियारों की आपूर्ति अपेक्षाकृत सीमित है। लेकिन कुछ अत्याधुनिक हथियारों के स्टॉक को लेकर दबाव है।

THAAD और Patriot मिसाइलों का स्टॉक चिंता का कारण

अमेरिकी हथियारों के भंडार को लेकर सबसे ज्यादा चिंता एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को लेकर सामने आई है। CNN के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने अपने थाड मिसाइल भंडार का करीब 80 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। वहीं, पैट्रियाट इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टॉक में भी लगभग 50 फीसदी की कमी आई है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास पैट्रियट सिस्टम के दो आधुनिक संस्करणों की करीब 2,200 मिसाइलें और लगभग 452 THAAD मिसाइलें थीं। यह आंकड़े अमेरिका के लिए इसलिए चिंतित करने वाली बात, ये दोनों मिसाइलें हवाई हमलों को रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं।

अमेरिका के घटते सैन्य भंडार से खाड़ी देशों की भी बढ़ी चिंता

अमेरिकी हथियारों के घटते भंडार का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों में भी इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। सऊदी अरब और कतर समेत कई देश अपनी हवाई सुरक्षा के लिए अमेरिकी रक्षा प्रणालियों पर काफी निर्भर हैं।खाड़ी देशों को डर है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज करता है और इसके जवाब में ईरान मिसाइल या ड्रोन हमले करता है, तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के भंडार में सीमित उपलब्धता उनके लिए चुनौती बन सकती है।

ट्रंप ने हथियारों की कमी के लिए बाइडेन को भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं

ट्रंप पहले भी अमेरिकी हथियारों के घटते भंडार के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उनका आरोप है कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार भेजे, जिससे अमेरिकी स्टॉकपाइल पर दबाव पड़ा।लेकिन गाजा और यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने इजरायल और यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइलें उपलब्ध कराई हैं, जिसके चलते उसके रक्षा उद्योग और हथियार भंडार पर भारी दबाव पड़ा है। फिलहाल,अमेरिकी प्रशासन अब रक्षा कंपनियों से हथियारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कह रहा है। ट्रंप ने इसके लिए सैन्य हथियार बनाने वाली कंपनियों से मीटिंग भी की है है।इससे पहले मार्च में भी ट्रंप ने रक्षा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। इसके अलावा जुलाई में उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हुए रक्षा कंपनियों को अधिक हथियार बनाने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

अमेरिकी नागरिकता पर ट्रंप ने फिर अपनाया कड़ा रुख, सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद भी इन दो आदेशों पर किए साइन

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने की कोशिश जारी रखे हुए है। इस मामले में ट्रंप ने नए सीमित दायरे वाले दो कार्यकारी आदेशों पर साइन भी किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वो एक बार फिर उन लोगों की संख्या को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश में पैदा होने पर अमेरिकी नागरिक बन सकते हैं। ये इस बात का संकेत है कि जन्म के अधिकार से नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को सीमित करने की उनकी पहली कोशिश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद भी, वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वो इमिग्रेशन पर दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इनमें से एक आदेश उन लोगों की संख्या को सीमित करता है जो अमेरिका में पैदा होने के बाद अमेरिकी नागरिकता के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि दूसरा आदेश लोगों को बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आने से रोकने पर केंद्रित है। नए आदेश के मुताबिक, कुछ खास श्रेणियों के बच्चों को खुदबखुद नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे-विदेशी दूतावासों या संगठनों से जुड़े लोगों के बच्चे, दुश्मन विदेशी (Alien Enemies) माने जाने वाले लोगों के बच्चे, जिनके माता-पिता ने नागरिकता हासिल करने के लिए धोखाधड़ी की हो।

साथ ही उन लोगों के वीजा पर प्रतिबंध बढ़ाना जो सिर्फ बच्चे को जन्म देने और उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाने के इरादे से अमेरिका आते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके नए फैसले संवैधानिक होंगे और इस मुद्दे को फिर से उठाने का उनका प्रयास अमेरिकी नागरिक बनने वालों को प्रतिबंधित करने के प्रशासन की सक्रियता को दिखाता है। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। दुर्भाग्य से, हमें एक बुरा फैसला मिला, बहुत अनुचित फैसला। इसकी वजह से हमारे देश को नुकसान होता है और हम इसे एक अलग तरीके से खत्म कर रहे हैं।" इमिग्रेशन के पक्षधर और कई कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि संविधान में यह साफ तौर पर बताया गया है कि किसे नागरिक माना जाएगा। उनका यह भी तर्क है कि जन्म के आधार पर नागरिकता से अमेरिका को फायदा होता है क्योंकि इससे देश के भविष्य में सभी की बराबर हिस्सेदारी बनती है। वहीं जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उन पिछली कोशिशों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि अमेरिका में गैर-कानूनी या अस्थायी तौर पर रह रहे लोगों के बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। दुर्भाग्य से, हमें एक बुरा फैसला मिला, बहुत अनुचित फैसला। इसकी वजह से हमारे देश को नुकसान होता है और हम इसे एक अलग तरीके से खत्म कर रहे हैं।"

दक्षिण अफ्रीका ने भारत में अपने राजदूत अनिल को वापस बुलाया, जैकब जूमा और अजय गुप्ता से मिलने का आरोप

वॉशिंगटन, एजेंसी। भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल को वापस बुला लिया गया है,। सूकलाल पर आरोप है कि वह पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा और भारतीय मूल के एक ऐसे विवादित बिजनेसमैन के बीच हुई बैठक में शामिल हुए थे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। अजय गुप्ता भारतीय मूल के विवादित दक्षिण अफ्रीकी व्यवसायी हैं जिनके वहां के कई शीर्ष राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध बताए जाते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लमोला ने बताया कि सूकलाल को विचार-विमर्श के लिए वापस बुलाया गया है। अफ्रीकी सरकार की ओर से यह कदम तब उठाया गया जब जैकब जुमा और सूकलाल की हरिद्वार में 26 जून को बिजनेसमैन अजय गुप्ता से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थीं। लामोला ने एक दिन पहले प्रिटोरिया में कहा, "हम यह कन्फर्म करते हैं कि उच्चायुक्त सूकलाल को आगे की बातचीत के लिए मुख्यालय वापस बुला लिया गया है।"

भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राजनयिक सूकलाल, भारत में उच्चायुक्त नियुक्त होने से पहले देश के G20 शेरपा और ब्रिक्स (BRICS) शेरपा थे। हालांकि अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने अपनी खबर में बताया कि सूकलाल से संपर्क करने पर, उन्होंने बताया कि यह महज "औपचारिकता" थी और "चिंता की कोई बात नहीं" है। उन्होंने कहा कि वह 2 दिन बाद दिल्ली लौट रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जूमा इस साल जून में निजी दौरे पर भारत आए थे और इस दौरान वह हरिद्वार भी गए थे, जहां उनकी मुलाकात दक्षिण अफ्रीकी राजदूत सूकलाल और व्यवसायी गुप्ता से हुई थी और तीनों की एक साथ की तस्वीरें भी ली गई थीं। इन तीनों को हरिद्वार के सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर में एक धार्मिक समारोह के दौरान एक साथ देखा गया था।

"सलाह-मशविरे" के लिए वापस स्वदेश बुलाया

दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री लमोला ने बुधवार को कहा कि सरकार ने सूकलाल को "सलाह-मशविरे" के लिए वापस स्वदेश बुलाया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग ने विदेश यात्रा करने वाले पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए राजनयिक मदद से जुड़े कड़े नियमों का प्रस्ताव दिया है। करीब एक दशक पहले, भारतीय मूल के गुप्ता बंधुओं पर तत्कालीन राष्ट्रपति जूमा के साथ अपने करीबी संबंधों का फायदा उठाने के आरोप लगे थे। चर्चा में आने के बाद गुप्ता परिवार ने साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया, क्योंकि एक न्यायिक आयोग ने इन आरोपों की जांच शुरू की थी कि वे "स्टेट कैप्चर" नाम से जुड़े एक बड़े घोटाले में शामिल थे।

साल 2022 में जूमा को पार्टी ने निकाला

जांच के दौरान आयोग ने साल 2022 में यह पाया कि जूमा ने अजय गुप्ता के 2 छोटे भाई, अतुल और राजेश- के कहने पर मंत्रियों को नियुक्त और बर्खास्त किया था। यह मामला सामने आने के बाद ज़ूमा को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) से निकाल दिया गया है। एक समय वह इस पार्टी की अगुवाई किया करते थे। लेकिन अब वह विपक्षी पार्टी 'उमखोंतो वे सिजवे' (uMkhonto weSizwe, MK)- जिसका मतलब है 'राष्ट्र का भाला' – के प्रमुख हैं।

मौजूदा हालात पर विदेश मंत्री लमोला ने कहा, "हमने संसद और राष्ट्रपति कार्यालय को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं ताकि पूर्व राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान प्रोटोकॉल और राजनयिक मदद के लिए एक नए ढांचे पर विचार किया जा सके।"

पूर्व राष्ट्रपतियों की यात्रा को लेकर नए नियम

अफ्रीकी सरकार की ओर से प्रस्तावित ढांचे के तहत, राष्ट्रपति कार्यालय और DIRCO ने नई अनिवार्य जानकारी व्यवस्था लागू की है जिसके तहत प्रोटोकॉल और राजनयिक मदद चाहने वाले पूर्व राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों को अपनी यात्रा से जुड़ी सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसमें यात्रा का मकसद, तय की गई गतिविधियां, फंडिंग के स्रोत, अहम मुलाकातें और वे किस हैसियत से यात्रा करेंगे, ये सारी जानकारी शामिल होंगी। लामोला का कहना है कि इन तरह की व्यवस्था लागू करने का मकसद यह तय करना है कि पूर्व नेता को लेकर ऐसी कोई धारणा न बने, जिससे कि वे दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इससे हमें ऐसी स्थिति से बचने में मदद मिलेगी, जब पूर्व राष्ट्रपति खुद को दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति का प्रतिनिधि बताने लगें, खासकर तब जब उन्हें वर्तमान राष्ट्रपति ने ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया हो।

बेंगलुरु में SIR के बाद आधे से ज्यादा मतदाताओं के कट सकते हैं नाम

बेंगलुरु। कर्नाटक में चल रहे मतदाता सूचियों के एसआईआर के दौरान सबसे बड़ी चिंता के रूप में उभरा है। घर-घर जाकर किए जा रहे सर्वेक्षण में शहर के लगभग आधे मतदाता एएसडीडीओ यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट, मृत और अन्य श्रेणी में आ गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बेंगलुरु शहरी जिले में 40.21 लाख मतदाता हैं और केवल 55.39% गणना फॉर्म ही सफलतापूर्वक डिजिटाइज किए जा सके हैं। शेष 44.61% यानी 17.93 लाख मतदाता एएसडीडीओ या असंघटित श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं। तीनों बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) जोनों में यह आंकड़े और भी अधिक हैं। बीबीएमपी दक्षिण में राज्य में सबसे अधिक ऐसे मतदाताओं का अनुपात दर्ज किया गया है, जहां 51.18% यानी 10.97 लाख मतदाता एएसडीडीओ या असंघटित के रूप में चिह्नित हैं। इसी तरह, बीबीएमपी मध्य में 47.85% यानी 9.04 लाख मतदाता और बीबीएमपी उत्तर में 46.95% यानी 10.95 लाख मतदाता इन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। बेंगलुरु के शहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 48.9 लाख से अधिक मतदाताओं को मौजूदा गणना प्रक्रिया के दौरान चिह्नित किया गया है, जो 19.93% के राज्य के औसत से काफी अधिक है। चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एएसडीडीओ श्रेणी में चिह्नित होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम अपने आप हट जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट, मृत या अन्य के रूप में वर्गीकृत मतदाताओं को सुधार या बहाली की मांग करने का अवसर मिलेगा। बूथ लेवल अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 8 अगस्त तक किसी भी गलत एएसडीडीओ मार्किंग को सुधार सकते हैं।

'अपमान सहने को भी तैयार', कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु विधानसभा में विजय और उदयनिधि के बीच जुबानी जंग

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु विधानसभा में मेकेदातु बांध विवाद और कावेरी जल बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के बीच तीखी बहस हुई। विधानसभा में DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने सीएम विजय से पूछा, 'सरकार को विधानसभा में यह साफ करना चाहिए कि कर्नाटक को मेकेदातु डैम पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।'

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम विजय ने कहा कि वे राज्य के किसानों और जनता के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम जो भी करना होगा, करेंगे। पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ

बातचीत के अपने प्रस्ताव का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यदि तमिलनाडु की जनता के भले के लिए उन्हें अपमानित भी होना पड़े, तो वे इसके लिए तैयार हैं।

पीएम मोदी को लिखा था पत्र

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि असेंबली ने मेकेदातु डैम के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा था। इसके बाद सीएम विजय ने DMK पर पलटवार करते हुए कहा कि 1969 में उनकी सरकार ने ही सबसे पहले कर्नाटक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी।

स्टालिन ने बैठक को लेकर टीवीके सरकार को घेरा

उदयनिधि स्टालिन ने मेकेदातु मुद्दे पर सर्वदलीय (ऑल-पार्टी) बैठक बुलाने से इनकार करने पर टीवीके सरकार को घेरा। स्टालिन ने कर्नाटक की राजनीतिक पार्टियों द्वारा एकजुट होकर मोर्चा बनाने का उदाहरण देते हुए कहा, 'कर्नाटक ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी दल एक टीम के रूप में एकजुट हो गए।'

सरकार क्यों हट रही पीछे?

विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया, ₹तमिल हितों की रक्षा और अपनी एकजुटता दिखाने के लिए टीवीके सरकार सर्वदलीय बैठक आयोजित करने से पीछे क्यों हट रही है?₹ इसके साथ ही, स्टालिन ने कर्नाटक सरकार से वार्ता के लिए मुख्यमंत्री विजय के बेंगलुरु जाने के प्रस्ताव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'सरकार ने पहले मुख्यमंत्री के बेंगलुरु दौरे की योजना खुद लीक की, लेकिन जब इसका विरोध हुआ, तो मुख्यमंत्री ने ऐसी किसी भी योजना से साफ इनकार कर दिया।'

सीएम विजय का बेंगलुरु जाने का प्रस्ताव

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विजय का बेंगलुरु जाने का एक प्रस्ताव था, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उनसे यह दौरा टालने का अनुरोध किया था। शिवकुमार ने कावेरी जल विवाद के कारण बढ़े तनाव और जारी विरोध प्रदर्शनों का हवाला दिया था। इसके साथ ही, उन्होंने विजय को माहौल अनुकूल होने पर कावेरी बेसिन के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का न्योता दिया था। कर्नाटक दौरे के अपने प्रस्ताव का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने पलटवार किया और पूछा कि पड़ोसी राज्य से बातचीत करने में क्या गलत है?

अपमानित होना पड़ा तो क्या होगा?

सीएम विजय ने कहा, 'जब शत्रु देश भी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, तो मैंने अपने पड़ोसी राज्य से संवाद करने का विचार किया। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इस कोशिश में हमें अपमानित होना पड़ा तो क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं कि अगर तमिलनाडु की जनता के हित के लिए मुझे अपमानित भी होना पड़े, तो मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं।'

सलमान निभाने वाले थे राम का किरदार, सीता के रोल में कास्ट हुई थीं सोनाली

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मगर इसके साथ ही सोहेल खान का एक अधूरी फिल्म 'रामायण' चर्चा में बनी हुई है।

अभिनेता-निर्देशक सोहेल खान भी पौराणिक कथा रामायण पर फिल्म बना रहे थे। इसमें उन्होंने सलमान खान को भगवान राम और सोनाली बेंद्रे को सीता के रोल में कास्ट किया था मगर फिल्म का निर्माण नहीं हो सका। जानें क्या थी इसकी वजह?

सोहेल खान के एक पुराना प्रोजेक्ट इन दिनों चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नब्बे के दशक में सोहेल भी महाकाव्य रामायण पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म की शूटिंग लगभग 40 प्रतिशत हो चुकी थी। फिल्म में सलमान खान जहां भगवान राम के किरदार में थे। वहीं सोनाली बेंद्रे माता सीता के रोल के लिए चुनी गई थीं।

पूजा भट्ट की वजह से रुका प्रोजेक्ट

सोहेल की फिल्म 'रामायण' में पूजा भट्ट को भी एक महत्त्वपूर्ण किरदार में थीं। मगर शूटिंग के दौरान सोहेल और पूजा की नजदीकियां बढ़ गईं। इसका खुलासा खुद पूजा ने एक इंटरव्यू में किया। सोहेल के पिता सलीम खान के दखल के बाद अभिनेता और पूजा के बीच रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। इसके बाद दोनों के प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगड़ गए और आखिरकार फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई।

कब रिलीज होगी नितेश तिवारी की 'रामायण'?

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म 'रामायण' मेगा बजट मूवी है, जिसे करीब 4000 करोड़ रुपये की लागत के साथ बनाया जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश समेत कई बड़े अभिनेता हैं। फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी। पहला हिस्सा इस साल दिवाली पर आएगा और दूसरा हिस्सा अगले साल दिवाली पर दस्तक देगा।

मिनी माथुर बनीं 'अलायंस' की विजेता, एली गोनी और रूही दोसानी को हराया; इनाम में मिली कितनी राशि?

रियलिटी शो 'अलायंस' की विजेता अभिनेत्री मिनी माथुर बनी हैं। जानिए, उन्होंने शो की ट्रॉफी हासिल करने के अलावा इनाम में कितनी राशि प्राप्त की है।

शो 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर ने टीवी एक्टर एली गोनी और यूट्यूबर रूही दोसानी को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। उन्हें ट्रॉफी के अलावा इनाम में 50 लाख रुपये मिल हैं। मिनी को उम्मीद है कि यह जीत आम महिलाओं को भी प्रेरित करेगी।

शो 'अलायंस' जीतने के बाद मिनी माथुर ने अपनी विनिंग स्पीच में कहा, 'इन छह हफ्तों में मैंने एक पूरी जिंदगी जी ली है। यह मेरा पहला रियलिटी शो है। इससे पहले मैंने कभी किसी ऐसे रियलिटी शो में हिस्सा लेने के बारे में नहीं सोचा था, जिसमें कंटेस्टेंट्स को एक जगह बंद रहना पड़ता है। मैंने हां इसलिए कहा क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिशन पसंद हैं। मुझे खुशी है कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इसके लिए मनाया। मुझे नहीं लगा था कि मैं यहां एक हफ्ते से ज्यादा टिक पाऊंगी क्योंकि जब जिंदगी अच्छी चल रही हो, तो आप उसे मुश्किल या असहज न बनाने के बहाने तलाशते हैं। लेकिन कुछ चीजें थीं जो मैं खुद को साबित करना चाहती थी। अपनी जिंदगी के बारे में कुछ चीजों पर फिर से सोच रही थी। लेकिन जब मैं यहां आई तो मुझे सबसे लगाव हो गया। मुझे हर एक कंटेस्टेंट से प्यार हो गया। इस पूरे सफर में उन्होंने मेरी बहुत मदद की।'

आगे की योजना भी मिनी ने साझा की

वह आगे कहती हैं, 'मुझे लगता है कि मैंने शो को गरिमा और शालीनता के साथ खेला। मुझे उम्मीद है कि मुझे देखकर सभी महिलाओं को थोड़ी प्रेरणा मिलेगी। मुझे लगता है कि अब आसमान ही मेरी लिमिट है। मैं खुद को और आगे ले जाऊंगी।'

शो में नजर आए थे कई सेलेब्स

'अलायंस' रियलिटी शो में रवि किशन, रीवा किशन, कुशाल टंडन और अर्सलान गोनी, जैद दरबार, डेजी शाह, निखिल चिनापा, रूही दोसानी और नीति टेलर, वंशज सिंह और डॉली जावेद, पायल धरे, सोहेल खान जैसे सेलेब्स नजर आए थे।

'बंटवारा 1947' को लेकर सनी देओल ने फैंस से की खास गुजारिश, बोले– आप फिल्म देखेंगे तो सब भूल जाएंगे

अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'बंटवारा 1947' का प्रमोशन कर रहे हैं। मुंबई में भी उन्होंने फिल्म का प्रमोशन किया था, इस दौरान मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत में फिल्म की कहानी, किरदार और इसके पीछे की मंशा का जिक्र किया। इसके अलावा फैंस से एक खास गुजारिश भी वह करते दिखे।

मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए सनी देओल ने कहा, 'किरदार ठीक वैसे ही हैं जैसे उन्हें लिखा गया था। हमने कभी भी किसी चीज को न्यूट्रल करने या मौजूदा माहौल के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की। यह बस वैसी ही कहानी है जैसी लिखी गई थी।

सनी देओल का यह भी कहना था कि दर्शक फिल्म देखते वक्त इतना खो जाएंगे कि धर्म या राजनीति से जुड़ी बहस कहीं पीछे छूट जाएगी। वह कहते हैं, 'जब आप फिल्म देखेंगे तो आप वह सब भूल जाएंगे। आप इस सफर में इतने शामिल हो जाएंगे कि फिल्म देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि बंटवारे का क्या मतलब था। मुश्किल हालात में खुद के और अपने अपनों के साथ खड़े होना कितना जरूरी था।'

क्या है 'बंटवारा 1947' फिल्म की कहानी?

'बंटवारा 1947' एक भावुक करने वाली कहानी है। यह भारत के बंटवारे के दर्द और उससे जुड़े इंसानी जज्बातों को करीब से दिखाएगी। फिल्म मुश्किल हालात में भी प्यार, हिम्मत, त्याग और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी कहेगी। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'बंटवारा 1947' में कई उम्दा कलाकार नजर आएंगे। फिल्म में सनी देओल के अलावा शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार दिखाई देंगे।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com